04 - बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों से किसे फायदा?

05 - आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी

A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 31 जुलाई, 2025

06 - ठेका कंपनी ने भी 2 किमी मेंटनेंस कर सड़क अधूरी छोड़ी

07 - रोपित पौधो के फोटोग्राफ्स जियो टैग सहित उपलब्ध कराएं...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 293, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

नई शिक्षा नीति : अमल में अभी भी कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं

फरीहा इफ्तिखार

भारत की शिक्षा प्रणाली को प्री-स्कूल से लेकर पीएचडी तक आधुनिक बनाने और इसे 'भारतीय मूल्यों' से जोड़कर रखने के उद्देश्य से, 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू की गई थी – वह भी कोविड महामारी के बीच। यह देश की तीसरी शिक्षा नीति थी, जिसे पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने तैयार किया था। इससे पहले दो नीतियां 1968 और 1986 में बनी थीं। NEP 2020 में कई अहम बिंदुओं पर ज़ोर दिया गया – जैसे शुरुआती स्तर पर पढ़ने-लिखने और गिनती की मजबूत समझ, मल्टीडिसिप्लिनरी यानी बहुविषयक शिक्षा, अनुभव आधारित सीखने, डिजिटल तरीकों से पढ़ाई, उच्च शिक्षा में नामांकन दर बढ़ाना, रिसर्च और कौशल आधारित ट्रेनिंग को बढ़ावा देना। इसके साथ ही मातृभाषा में शिक्षा, भारत के पारंपरिक ज्ञान को आगे बढ़ाना और शिक्षा व्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार जैसे लक्ष्य भी तय किए गए।

हालांकि, नीति के लागू होने के पांच साल बाद, जबकि इसमें सुझाई गई कई योजनाएं अब जमीनी स्तर पर चल रही हैं, उनका अमल पूरे देश में समान नहीं है। राज्यों, क्षेत्रों और संस्थानों के हिसाब से इसमें काफी फर्क दिख रहा है। कई जगहों पर इसका कार्यान्वयन बिखरा हुआ और असंगत है।

नीति के एक बड़े प्रस्ताव – उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई), जिसे देशभर में उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत नियामक संस्था बनना था, उस पर अब तक अमल नहीं हुआ है। इसके विधेयक को भी अभी सरकार ने अंतिम रूप नहीं दिया है।

हालांकि, शिक्षा व्यवस्था धीरे-धीरे NEP 2020 के लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि भारत जैसे विविधता भरे देश में, जहां शिक्षा एक साझा (संविधान की समवर्ती सूची में) विषय है, वहां बड़े पैमाने पर बदलाव के नतीजे आने में अभी समय लगेगा।'

शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञ मीता सेनगुप्ता ने कहा, 'हमारे जैसे देश में, जहां हम ज़्यादा ढांचागत सिस्टम के आदी हैं, वहां शैक्षणिक आज़ादी और खोज की सोच कुछ लोगों को असामान्य या असहज लग सकती है' यही वजह है कि कई लोगों को संदेह है कि यह सफल होगी भी या नहीं, या इसे उतनी सख्ती से लागू किया जा सकेगा या नहीं।'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की शुरुआत से ही इसे लेकर विवाद होते रहे हैं। नीति के लागू होने के तुरंत बाद विपक्ष शासित राज्यों ने इसमें दिए गए तीन-भाषा फॉर्मूले पर आपत्ति जताई, जिसके तहत छात्रों को कक्षा 8 तक तीन भारतीय भाषाएं और अगर संभव हो तो कक्षा 10 तक सीखनी होंगी। दक्षिण भारतीय राज्य, खासकर तमिलनाडु, इस पर आपत्ति जताता रहा। राज्य ने इसे 'हिंदी थोपने' की कोशिश करार दिया। हालांकि, NEP2020 में किसी खास भाषा को अनिवार्य या प्राथमिकता देने की बात नहीं की गई थी। जून में महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला वापस ले लिया क्योंकि विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया था। हालांकि, महाराष्ट्र ने बाकी हिस्सों में NEP 2020 को लागू किया है। लेकिन यह बात ध्यान देने की है कि तीन-भाषा फॉर्मूला NEP 2020 से पहले भी मौजूद था। यह 1968 की शिक्षा नीति से ही लागू है। इस समय, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश NEP 2020 को चरणबद्ध तरीके से अपना रहे हैं. मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इन तीन राज्यों को NEP लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह राज्यों को किसी खास सरकारी नीति को अपनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।

NEP 2020 का एक अहम फोकस यह है कि कक्षा 5 तक और अगर संभव हो तो कक्षा 8 तक, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में पढ़ाई कराई जाए। क्योंकि कई अध्ययनों से पता चला है कि बच्चे अपनी भाषा में जल्दी और बेहतर समझ पाते हैं, खासकर कठिन और जटिल विषयों को। पिछले पांच साल में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की हैं। सीबीएसई ने स्कूलों से कहा है कि वे छात्रों की भाषा मैपिंग करें और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई शुरू करें।

यह सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है. सरकार ने तकनीकी और मेडिकल कोर्स भी स्थानीय भाषाओं में शुरू किए हैं. हालांकि, इसके साथ ही यह चिंता भी जताई जा रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं में पेशेवर कोर्स करने वाले छात्रों को नौकरी के अवसरों में कठिनाई हो सकती है।

सितंबर 2022 में जब केंद्र सरकार ने पीएम-श्री (PM Schools for Rising India) योजना की घोषणा की, तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल के साथ उसका टकराव और गहरा हो गया। इस योजना का मकसद मौजूदा स्कूलों को मॉडल संस्थानों में बदलना है, जो NEP 2020 की सोच को दर्शाते हों और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जानी थी। लेकिन इस योजना में शामिल होने के लिए एक अहम शर्त थी – राज्यों को केंद्र सरकार के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने होते, जिसके ज़रिये वे NEP को अपनाने के लिए सहमत होते। इन तीनों राज्यों ने इस शर्त को 'थोपे जाने जैसा' मानते हुए इसका विरोध किया और समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि इन राज्यों को केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा योजना समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत मिलने वाली फंडिंग रोक दी गई, क्योंकि पीएम-श्री योजना इसी अभियान के तहत आती है। 21 जुलाई को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2024-25 शैक्षणिक सत्र में इन तीनों राज्यों को SSA के तहत कोई फंड जारी नहीं किया गया है। दिल्ली और पंजाब जैसे कुछ अन्य राज्यों ने भी शुरुआत में इस शर्त का विरोध किया था, लेकिन जब उनकी SSA फंडिंग रोकी गई, तो उन्होंने आखिरकार Mo पर हस्ताक्षर कर दिए।

नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF), जो स्कूल शिक्षा और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज़ है, इसका पहला एडिशन 2022 में फाउंडेशन स्टेज के लिए और बाकी स्कूल स्तर के लिए 2023 में जारी किया गया। इस दस्तावेज़ में भारतीय संदर्भ को शिक्षा में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है, ताकि देश की संस्कृति पर गर्व की भावना विकसित हो सके।

2022 में दिशा-निर्देश जारी करते समय, शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा था कि NCF का मकसद है भारत की शिक्षा प्रणाली को उपनिवेशवाद से मुक्त करना। पिछले साल से लेकर इस साल तक, NCERT ने कक्षा 8 तक की नई किताबें जारी की हैं।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

बारिश संकट

सजग रहें, ऐहतियात बरतें सबकी व्यवस्था करें

- **सीएम बोले-वर्षा प्रभावितों को भोजन-पानी,रहवास और दवा सब मिले**
- **वर्षा से किसी को कठिनाई न हो,सेवाभाव से सबकी सुरक्षा पर दें ध्यान**

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जान-माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित होमगार्ड, आपदा प्रबंधन दल सब मिल जुलकर पूरी सजगता और सतर्कता से कार्य करें। राहत एवं बचाव दल पूरी तैयारी से रहें और जरूरमंदों तक तत्काल सभी प्रकार की मदद पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को होमगार्ड मुख्यालय स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष (स्टेट कमांड सेंटर) पहुंचकर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के चलते उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी ली और जन सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री जे.एन. कंसोटिया, पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना, डीजी होमगार्ड सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव, एडीजी श्री ए. सांई मनोहर, सचिव एवं आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि प्रदेश में बीते तीन दिनों से भारी वर्षा हो रही है। भारी वर्षा के चलते प्रदेश के कुछ जिलों में गांव और घरों में पानी भर जाने जैसी उत्पन्न परिस्थितियों में अब तक 2900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रदेश में जहां-जहां अतिवर्षा की सूचना और लोगों के बाढ़ के पानी फंस जाने की जानकारी मिली है, वहां पूरी क्षमता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं।

जीवन बचाने में मददगारों को पुरस्कृत किया जायेगा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि वे सभी तरह का ऐहतियात बरतें। आपदा नियंत्रण के सभी इंतजाम तैयार रखें। बाढ़ आने की स्थिति में तत्काल लोगों का रेस्क्यू करें। उन्होंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि बाढ़ का पानी कम होते ही जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे करा लें और अतिवर्षा तथा बाढ़ से जो भी नुकसान हुआ है, उन्हें समुचित मुआवजा देने के लिए विधिवत प्रस्ताव तैयार कर लें। सरकार हर बाढ़ पीड़ित की भरपूर मदद करेगी। कलेक्टर्स ने बताया कि लोगों को बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों से सुरक्षित निकालने में सामाजिक संगठनों ने भी मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित निकालकर उनका जीवन बचाने में मदद करने वाले लोगों की सूची तैयार कर लें, सरकार ऐसे साहसी, परोपकारी और मददगार लोगों को आगामी 15 अगस्त और अन्य अवसरों पर भी सम्मानित करेगी। इन्हें पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर संभाग के गुना, शिवपुरी, दतिया और अशोकनगर, सागर संभाग के सागर, दमोह, छतरपुर,

तेज बहाव वाले किसी भी पुल-पुलिया से आवागमन न करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे वर्षा थमने तक बेहद सतर्क रहें, सजग रहें। बाढ़ प्रभावितों को बचाने में मदद भी करें। उन्होंने कहा कि नागरिक बाढ़ वाले नदी-नाले में उतरने से बचें और तेज बहाव वाले किसी भी पुल-पुलिया से आवागमन कतई न करें। उन्होंने कहा कि बारिश में करंट फैलने की आशंका के चलते बिजली के तार खुले न छोड़े जाएं। उन्होंने कहा कि कच्चे मकान में रहने वाले सावधानी बरतें, क्योंकि अति वर्षा से इनके क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है। मुख्यमंत्री ने कलेक्टर्स से कहा कि जिन लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उनके सुरक्षित निवास, भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवा, कपड़े और अन्य जरूरतों की भी समुचित व्यवस्था कर सभी पीड़ितों को उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा की स्थिति में सरकार हर पीड़ित के साथ है, किसी को भी असहाय नहीं रहने दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिलों में बचाव दल के अधिकारियों और कलेक्टर्स से चर्चा कर उनके क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति, रेसक्यू ऑपरेशन्स की अपडेट सहित पीड़ितों को प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही राहत के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। लोगों को बचाने में सरकार प्रशासन, सेना, आपदा प्रबंधन दल सब साथ हैं। बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित निकालने में कोई भी कमी न रखें।

यदि उनके जिले में अतिवर्षा का अलर्ट आया है, तो आवश्यकता के अनुरूप स्कूली बच्चों की छुट्टी आदि भी घोषित कर दें, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका ही न रहे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मौसम विभाग की चेतावनी का जिक्र करते हुए कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर्स हाई अलर्ट पर रहें और किसी भी क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होने की जानकारी मिलते ही राहत एवं बचाव दल को तत्परतापूर्वक वहां पहुंचाएं।

सुप्रभात

सारे ठौर ठिकाने बदले,
मगर नहीं याराने बदले।
मंदिर बदले मस्जिद बदलीं,
लेकिन कब मयखाने बदले।
बारिश धूप कि बरसे पत्थर,
नहीं कभी दीवाने बदले।
कभी नहीं बदली दस्तारें,
हाथों के दस्ताने बदले।
ना बदले खिड़की दरवाज़े,
ना घर के वीराने बदले।
क्या करते तक़दीर ने ही जब,
लिखे हुए अफ़साने बदले ।
कभी न बदली आबोहवा और,
कभी न आबो दाने बदले।

- सुरेन्द्र चतुर्वेदी

- **इसरो-नासा का सबसे महंगा और ताकतवर**

सैटेलाइट 'निसार' लॉन्च

श्रीहरिकोटा (एजेंसी)। अब तक के सबसे महंगे और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार को आज यानी, बुधवार 30 जुलाई को लॉन्च किया गया। इस मिशन पर 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसे इसरो और नासा ने मिलकर बनाया

है। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5.40 बजे जीएसएलवी-एफ 16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। रॉकेट ने निसार को 743 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूरज के साथ तालमेल वाली सन-सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया। इसमें करीब 18 मिनट लगे। निसार 747 किमी की ऊंचाई पर पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पोलर ऑर्बिट एक ऐसी कक्षा है जिसमें सैटेलाइट धरती के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है। इस मिशन की अवधि 5 साल है। यह पहली बार है जब जीएसएलवी रॉकेट से उपग्रह को सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया गया। निसार एक हाई-टेक सैटेलाइट है। इसका पूरा नाम सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो ने मिलकर बनाया है। इस मिशन पर 1.5

- **घने जंगल और अंधेरे में देखने की क्षमता,97 मिनट में धरती का चक्कर पूरा करेगा**

बिलियन डॉलर यानी करीब 12,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये सैटेलाइट 97 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेगा। 12 दिनों में 1,173 चक्कर लगाकर यह पृथ्वी की लगभग हर इंच जमीन को मैप कर लेगा। इसके पास बादलों, घने जंगल, धुएं और यहां तक कि अंधेरे में भी देखने की क्षमता है। यह धरती की सतह पर बहुत छोटे बदलावों को भी देख सकता है। निसार मिशन का मुख्य मकसद है धरती और उसके पर्यावरण को करीब से समझना। ये सैटेलाइट खास तौर पर तीन चीजों पर नजर रखेगा। ये देखेगा कि धरती की सतह या ग्लेशियर्स में कितना बदलाव हो रहा है। जैसे जमीन का धंसना या बर्फ का पिघलना। जंगलों, खेतों और दूसरी प्राकृतिक जगहों की स्थिति को मॉनिटर करेगा, ताकि ये समझा जा सके कि पर्यावरण कैसा है।

बाढ़-बारिश से बुरे हाल लोगों का जीना मुहाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में भारी बारिश का दौर जारी है। राजस्थान में बुधवार को भी 6 जिलों में बारिश का रेड और बाकी में यलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी के बीच 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी है। मंगलवार देर रात से सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं। यहां श्योपुर (मध्य प्रदेश) को जोड़ने वाली एक पुलिया बह गई। शहर के कई इलाके पानी में डूब गए। घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। बहाव इतना तेज था कि गाड़ियां बहते हुए एक-दूसरे पर चढ़ गईं।

बुधवार सुबह से रेस्क्यू टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर, श्योपुर, विदिशा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। कई रास्ते भी बंद हो गए। बुधवार को भी तेज बारिश का अलर्ट है। इसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, सीहोर, अशोकनगर में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इधर, हिमाचल के मंडी में सोमवार रात बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मलबे में दबे 20 लोगों को बचाया गया। मंडी में अभी भी 254 सड़कें बंद हैं। वहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में 357 से ज्यादा सड़कें बंद हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 35 °c
न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 31 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

ट्रम्प ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का किया ऐलान

कहा-भारत रूस से हथियार-तेल खरीद रहा, इसलिए जुर्माना भी वसूलेंगे,1 अगस्त से लागू

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार को भारत पर 1 अगस्त से 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि भारत, रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। ट्रम्प ने एक और पोस्ट में कहा कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है, इसलिए वे भारतीय सामानों पर टैरिफ लगा रहे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड डील करने की इच्छा जताई थी। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से यह डील पूरी नहीं हो पाई। भारत पर टैरिफ का कारण रूस के साथ ऊर्जा और सैन्य समझौते को भी माना जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है, इसलिए ये कार्रवाई जरूरी है। वहीं ट्रंप ने भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। व्यापार में भी कई मुश्किलें पैदा करता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूस से ऊर्जा और हथियार खरीदने के लिए भारत को अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। ट्रम्प ने एक पोस्ट में लिखा, याद रखें, भारत हमारा दोस्त है। लेकिन, सालों से हमने उनके साथ बहुत कम व्यापार किया है। क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा। और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा मुश्किल और खराब गैर-मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं। इसका मतलब है कि भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। अब देखना यह है कि भारत इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। ट्रंप ने आगे कहा,वे (भारत) हमेशा रूस से ही ज्यादातर सैन्य उपकरण खरीदते रहे हैं। और चीन के साथ, वे रूस के सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार हैं। ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्या करना बंद करे - ये सब अच्छी बातें नहीं हैं!

एलओसी के पास सेना का ऑपरेशन शिवशक्ति

तीन हथियार और गोला-बारूद भी बरामद

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल (एलओसी) के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सेना ने मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक, बॉर्डर पर तैनात जवानों ने मंगलवार देर रात देगवार सेक्टर के मालदीवलन इलाके में संदिग्ध गतिविधि देखी जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। इस ऑपरेशन को शिवशक्ति नाम दिया गया। आतंकियों के पास से 3 हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया। पिछले तीन दिनों में सेना का यह दूसरा एनकाउंटर है।

डीजीसीए ऑडिट में एअर इंडिया से जुड़ी 100 गड़बड़ियां मिलीं

● इनमें 7 बेहद गंभीर जोखिम की

नई दिल्ली (एजेंसी)। विमानों की सुरक्षा देखने वाली संस्था नागरिक उड्डयन महा निदेशालय ने टाटा समूह की एयरलाइन एअर इंडिया में कई बड़ी खामियां पकड़ी हैं। सूत्रों के मुताबिक इनमें पायलटों और केबिन क्रू की ट्रेनिंग, उनके आराम और ड्यूटी के नियम और उड़ान भरने-उतरने से जुड़े मानकों में करीब 100 तरह की गड़बड़ियां शामिल हैं। हालांकि, रॉयटर्स के मुताबिक, ये संख्या 51 है। इनमें से 7 गड़बड़ियां लेवल-1 की हैं। ये सबसे गंभीर सुरक्षा जोखिम हैं और एयरलाइन को इन्हें 30 जुलाई तक ठीक

करना होगा। बाकी बाकी 44 खामियों को 23 अगस्त तक सुधारने को कहा गया है। हालांकि, अभी इन खामियों की लिस्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। एअर इंडिया ने एक बयान में इन ऑडिट नतीजों को स्वीकार किया है और कहा है कि वे तय समय के अंदर डीजीसीए को अपना जवाब देंगे। डीजीसीए एअर इंडिया के गुरुग्राम में बने मुख्य सेंटर पर 1 से 4 जुलाई तक एक बड़ा ऑडिट हुआ था। इसमें फ्लाइट ऑपरेशन, शेड्यूल बनाने, रोस्टरिंग और कई दूसरे पहलुओं की जांच की गई थी। 23 जुलाई को एअर इंडिया को चार कारण बताओ नोटिस भेजे थे।

कैश कांड

जांच कमेटी की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो तभी क्यों नहीं आए

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका व्यवहार भरोसे के लायक नहीं है और पूछा कि अगर उन्हें जांच समिति की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो उन्होंने उसी वक्त उसे चुनौती क्यों नहीं दी। बेंच में शामिल जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि जस्टिस वर्मा को पहले ही सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, न कि अब जब जांच समिति ने उन्हें

दोषी पाया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि महाभियोग संसद की प्रक्रिया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा महाभियोग की सिफारिश किया जाना गलत है। दरअसल, जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका में इन-हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की गई है। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया है। घर से नोट मिलना साबित नहीं करता कि ये मेरे थे 18 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अपना अलग तर्क दिया था।

ऑपरेशन सिंदूर चर्चा

आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती

● नड्डा बोले-2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे,यूपीए सरकार मिठाई खिलाती रही

● खड़गे ने चला दांव,कहा-लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना,न कि किसी को दोष देना

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद में मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार दूसरे दिन चर्चा हो रही है। भाजपा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि 2014 से पहले हर जगह बम ब्लास्ट होते थे, लेकिन यूपीए सरकार आतंकियों को मिठाई खिलाती रही। वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा- हम पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने लाए। खून-पानी एक साथ नहीं चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में बहस मंगलवार को जबकि लोकसभा में शुरू हुई थी। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा सहित कई सांसदों ने भाग लिया। खड़गे ने कहा- लीडरशिप का मतलब है जिम्मेदारी लेना, न कि किसी को दोष देना। वे (मोदी) जवाब नहीं देंगे, वे अपने दोस्तों-मंत्रियों से कहेंगे कि जाओ जो कहना है कहो। 11 साल में कभी बहस में शामिल नहीं होते। एक व्यक्ति को इतना बढ़ावा मत दो, भगवान मत बनाओ। लोकतांत्रिक रूप से आया है, उसे इज्जत दो, पूजा मत करो। जेपी नड्डा ने कहा कि 2004-2014 का समय देखिए, उस वक्त की सरकार ने कई आतंकी घटनाओं पर कोई एक्शन नहीं लिया। यूपीए के गृहमंत्री कहते थे कश्मीर जाने में डर लगता था। 2005 में श्रमजीवी ब्लास्ट हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। उस समय की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। पहलगाम पर सवाल उठाने वाले पहले अपने गिरेबां में झांक कर देखें। जेपी नड्डा ने कहा कि यूपीए के गृहमंत्री कहते थे कश्मीर जाने में डर लगता था। आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमले होते रहे हम बिरयानी खिलाते रहे। वो आतंकी हमले करते हम डोजियर भेजते रहे। यूपीए सरकार के दौरान जगह-जगह बम धमाके होते थे। पहलगाम पर हमले की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी चाहिए। विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि हाफिज सईद को जी कहकर बुलाते थे। सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि इसी सदन में छाती ठोक के बोला गया था।

यूएन ने माना-पहलगाम हमले के लिए टीआरएफ जिम्मेदार

कहा-आतंकी संगठन ने अटैक की 2 बार जिम्मेदारी ली,लश्कर का भी नाम आया

नई दिल्ली (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सेंक्शंस मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिस्ट संगठनों पर बुधवार को रिपोर्ट जारी की। इसमें माना कि पहलगाम हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) जिम्मेदार है। TRF ने हमले के बाद दो बार जिम्मेदारी ली। TRF ने हमले वाले दिन 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी प्रकाशित की थी। अगले दिन फिर से जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया। इसके बाद TRF ने कोई और बयान नहीं दिया और किसी अन्य संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। संयुक्त राष्ट्र की यह 36वीं रिपोर्ट आतंकी संगठनों ISIL, अल-कायदा और उनसे जुड़े गुटों पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक, एक सदस्य देश ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) की मदद के बिना संभव नहीं था। TRF और LeT के बीच संबंध हैं। जबकि एक अन्य सदस्य देश ने LeT को निष्क्रिय बताया और इन दावों को खारिज किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पहलगाम क्षेत्र में हालात बहुत संवेदनशील हैं और आतंकवादी संगठन इस तनाव का फायदा उठाने की फिर कोशिश कर सकते हैं।

पहलगाम की बायसरन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थी। इस दौरान 1 नेपाली नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हो गई थी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 अप्रैल को एक प्रेस बयान जारी कर आतंकवादी हमले की निंदा की थी, लेकिन उसमें TRF का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने बताया था कि हमने TRF का नाम हटवाने की कोशिश की थी और उसे सफलतापूर्वक हटा भी दिया गया था। इससे पहले 18 जुलाई को अमेरिका ने पाकिस्तान समर्थित द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) की लिस्ट में डाल दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसकी जानकारी दी थी। मार्को रुबियो ने बयान में लिखा था, लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक मुखौटा और प्रॉक्सी, TRF ने 22 अप्रैल, 2025 को भारत के पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। यह 2008 में मुंबई हमलों के बाद लश्कर का भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। TRF ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है, जिनमें 2024 का हमला भी शामिल है।

मोदी सीजफायर पर बोलेंगे तो ट्रम्प सच्चाई बता देगा

● राहुल गांधी ने कहा-ट्रेड डील पर इनको और दबाएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा, अगर पीएम मोदी सीजफायर पर बोलेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प खुल के बोलेगा। उनकी सारी सच्चाई बता देगा। राहुल ने कहा, ट्रम्प सीजफायर

पर लगातार इसलिए बयान दे रहा है, क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है। ट्रम्प ट्रेड डील को लेकर इनको (भारत) दबाएगा। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनी है। इससे पहले, पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ट्रम्प का नाम लिए बिना कहा था कि दुनिया के किसी देश और नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ ऐक्शन रोकने नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की गुहार लगाने के बाद सीजफायर हुआ।

रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप

● 8.8 रही तीव्रता, 5 मीटर ऊंची सुनामी उठीं, इमारतें ध्वस्त

अमेरिका के अलास्का-हवाई-कैलीफोर्निया तक लहरें पहुंची

मास्को (एजेंसी)। रूस के पूर्वी प्रायद्वीप कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया है। स् जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 8.8 थी। यह भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह 4.54 बजे आया। रॉयटर्स के मुताबिक कामचटका में 5 मीटर तक ऊंची सुनामी आई है। इसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र जमीन से 19.3 किलोमीटर की गहराई में था। कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि आज का भूकंप दशकों में सबसे शक्तिशाली था। उन्होंने कहा कि एक किंडरगार्टन स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जापान के टेलीविजन के मुताबिक, देश के पूर्वी तट के पास एक फुट ऊंची पहली सुनामी लहरें पहुंची हैं। जापान ने राजधानी टोक्यो में 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। इसके अलावा अपने फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर को खाली को करा लिया है। अमेरिका के अलास्का और हवाई द्वीप तक सुनामी की लहरें पहुंच गई हैं। अमेरिका ने हवाई राज्य के लिए जारी सुनामी चेतावनी को अब डाउनग्रेड कर एडवाइजरी में बदल दिया गया है।

अब दमिश्क में भी दिल्ली की दस्तक

● क्या असद की तरह कश्मीर पर भारत का साथ देंगे अल-जोलानी?

दमिश्क (एजेंसी)। भारत ने सीरिया की नई सरकार के साथ डिप्लोमेटिक संबंध बहाल कर लिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय मे पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार ने सीरियाई विदेश मंत्री असद हसन अल-शिबानी से दमिश्क में मुलाकात की है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में भारत-सीरिया संबंधों को गहरा करने और आपसी हितों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सीरिया में अब कभी आईएसआईएस से संबंध रखने वाले अल-जोलानी की सरकार है, जो देश के राष्ट्रपति हैं।

अनोखी शादी ! स्कॉर्पियो छोड़ नाव से बारात ले गया दूल्हा

● 35 किमी की यात्रा में लगे 8 घंटे,फिर नाव से ही लाया दुल्हन

भागलपुर (एजेंसी)। बिहार के भागलपुर जिले में एक दूल्हा लग्जरी कार की जगह नाव पर अपनी बारात लेकर निकला। यह पूरा दृश्य जिले के पीरपैंती प्रखंड के बाकरपुर गांव का है। यहां 2 सप्ताह पूर्व से गंगा नदी में आई बाढ़ के पानी से बाकरपुर पंचायत पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में, इस गांव के देवमुनी कुमार सजधज कर दूल्हा बने तो 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ी। दरअसल बिहार और नेपाल में हो रही बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। गंगा और कोसी नदी कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से उपर बह रही हैं। कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। लड़के के पिता रामदेव मंडल ने बताया कि शादी की तिथि एक महीने पहले निर्धारित कर ली गई थी। इसी बीच गंगा नदी में भीषण बाढ़ आ गई। बाखरपुर गांव भी बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गया, गांव से निकलने का रास्ता नहीं बचा तो कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के कटाकोष गांव निवासी रामचंद्र चौधरी के यहां बारात नाव से गया। और शादी कर दुल्हन को लेकर नाव से ही वापस आया। दूल्हे राजा देवमुनी कुमार ने बताया कि गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण लड़की के घर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा। ऐसे में नाव पर बारात को ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि बारात में 25 से 30 लोग शामिल थे। दूल्हे राजा देवमुनी कुमार ने बताया कि वे घर से सज धज कर बारात लेकर कुछ दूर तो स्कॉर्पियो से गए, वहां से पैदल गंगा किनारे गए। फिर वहां से नाव अपने बाराती को साथ लेकर लड़की के घर कटिहार पहुंचे। घर से जब निकले तो आसमान साफ था, लेकिन जब नाव पर सवार हुए तो बारिश होने लगी तो भीगते हुए लड़की के घर पहुंचे।

अब बिहार की एक लाख आशा कार्यकर्ताओं को नीतिश का गिफ्ट

1 हजार की जगह मिलेंगे 3000, ममता को 300 की जगह 600, तेजस्वी बोले-मेरी नकल कर रहे

पटना (एजेंसी)। चुनाव से पहले नीतिश सरकार ने बिहार में आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने बुधवार सुबह एक्स पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, आशा कार्यकर्ताओं को अब 1 हजार रुपए की जगह 3 हजार रुपए प्रोत्साहन

राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। सीएम ने आगे लिखा, नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जर्जर मार्ग पर मुरम डालने का काम शुरू

खाचरौद। (ऋतुराज बुड़ावनवाला) सकतखेड़ी-भानपुर मार्ग पर ग्रामीणों के भारी रोष के चलते किए गए चक्काजाम आंदोलन के मध्य खाचरौद एसडीएम नेहा साहू की पहल पर जिला पंचायत सदस्य गजेन्द्र सिंह केसरिया,चापानेर पंचायत सरपंच कमलेश धाकड़, उपसरपंच भगवतसिंह ने अपनी निजी जिम्मेदारी पर तत्परता से गड्ढों को भरने के लिए मुरहम डालने का कार्य चालू करवाया। इस मार्ग पर स्थित खेतों पर निवास करने वाले शिवलाल मदारा, राजेश मदारिया, गोपाल धनोरा तथा दिनेश धनोरा ने बताया कि खाचरौद क्षेत्र के डेढ़ किलोमीटर के गड्ढे भरने का कार्य चालू हो गया है। प्रशासन द्वारा मार्ग की सुध लेने से बरसात के इस दौर में यह मार्ग सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से नौनिहालों तथा राहगीरों को राहत मिलेगी। भानपुर के जितेन्द्रसिंह डोडिया के अनुसार दो दिन बाद आलोट क्षेत्र की और के डेढ़ किलोमीटर के गड्ढे भरने के लिए मुरम डालने का काम चालू हो जाएगा। दोनों विधानसभा के ग्रामवासियों ने बरसात के बाद इस रोड को पक्का बनाने की मांग खाचरौद के विधायक तेजबहादुर सिंह चौहान तथा आलोट के विधायक चिंतामणि मालवीय से की।

राजवाड़ा सर्कल पर चला सफाई अभियान

इंदौर। इंडियन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट (आईसीएसआई) के इंदौर चैप्टर द्वारा नगर निगम इंदौर के सहयोग से मंगलवार सुबह 8:30 बजे राजवाड़ा सर्कल पर स्वच्छ भारत अभियान का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम आईसीएसआई द्वारा आयोजित स्टूडेंट मंथ के अंतर्गत संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि नगर निगम के अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया। अभियान का उद्देश्य छात्रों एवं युवाओं को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करना और उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ना रहा। आईसीएसआई के छात्र-छात्राओं, सदस्यों और नगर निगम कर्मचारियों ने मिलकर राजवाड़ा क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर नगर निगम द्वारा लगातार आठवीं बार स्वच्छता में देश में पहला स्थान पाने पर सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। महिला सफाई कर्मचारियों को साड़ी वितरित कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आईसीएसआई इंदौर चैप्टर के चेयरमैन सीएस अमित कुमार बारंगे, सचिव सीएस मनीष जोशी सहित अन्य पदाधिकारी और नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अखिलेश उपाध्याय विशेष रूप से उपस्थित रहे।

इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग को मिले नए आधुनिक उपकरण

वृक्षों की छंटाई, घास कटाई और पौध संरक्षण में सहयोग

इंदौर। नगर निगम इंदौर के उद्यान विभाग ने शहर के हरियाली संधारण कार्य को प्रभावी, आधुनिक और तकनीकी बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देशन में उद्यान विभाग को आधुनिक मशीनों एवं उपकरणों से सुसज्जित किया गया। वृक्षारोपण,पौध संरक्षण और उद्यान संधारण जैसे कार्यों के लिए पोलशा मशीन, लॉनमोर, ब्रश कटर, कीटनाशक, गमले और नर्सरी सामग्री वितरित की गई। इस वितरण कार्यक्रम का आयोजन जनकार्य एवं उद्यान प्रभारी राजेंद्र राठौर के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्होंने कहा, हरियाली शहर की पहचान है और उसे सुरक्षित रखने के लिए आधुनिक संसाधन महत्वपूर्ण हैं। इससे कर्मचारियों का काम सुरक्षित,प्रभावी और समय पर पूरा होगा। पोलशा मशीन विशेष रूप से ऊँचे वृक्षों की डगालों की छंटाई के लिए उपयोगी साबित होंगी। वहीं,लॉनमोर और ब्रश कटर से उद्यानों की घास को बेहतर ढंग से काटा जा सकेगा। इन मशीनों से न केवल श्रम की बचत होगी बल्कि संधारण कार्यों की गुणवत्ता में भी इजाफा होगा। इस अवसर पर अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर,उद्यान अधिकारी नागेंद्र सिंह भदौरिया समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी गार्डन सुपरवाइजरों को ये उपकरण सौंपे गए ताकि वे अपने क्षेत्रों में इनका प्रभावी उपयोग कर सकें।

फर्जी ऋण पुस्तिका से जमानत कराने वाला पकड़ाया

इंदौर। फर्जी ऋण पुस्तिका के जरिए कोर्ट से जमानत दिलाने वाले गिरोह के खिलाफ इंदौर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई। इस सिलसिले में तीन साल से फरार चल रहे आरोपी अकरम उर्फ बिजली (35), निवासी हिना पैलेस, खजराना को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह बीते दस साल से फर्जी दस्तावेज तैयार कर गंभीर अपराधों के आरोपियों को जमानत दिलवाने का रैकेट चला रहा था। अब तक इस प्रकरण में कुल 37 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस गिरोह से जुड़े केदार डाबी ने पत्रकार कल्पेश याग्निक आत्महत्या मामले में आरोपी सलोनी अरोरा की जमानत में भी फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया था, जिसके चलते दोनों के खिलाफ अलग से मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। एसआईटी का गठन पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में किया गया था। जिसकी अगुवाई एसीपी देवेंद्र सिंह धुर्वे कर रहे हैं। गिरोह के विरुद्ध आईपीसी की धाराएं 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है।

महापौर परिषद के नए सचिव डॉ. सगर बने

इंदौर। नगर पालिक निगम इंदौर में प्रशासनिक कार्यों की सुगमता और प्रभावी संचालन को ध्यान में रखते हुए बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सोमवार को आदेश जारी कर उपायुक्त डॉ. केशव सिंह सगर को महापौर परिषद का नया सचिव नियुक्त किया है। यह जिम्मेदारी अब तक जनसंपर्क अधिकारी एवं सचिव राजेंद्र गरोठिया के पास थी। उन्हें इस दायित्व से मुक्त करते हुए अब डॉ. सगर को परिषद के सचिव के रूप में कार्य सौंपा गया है। आदेश के अनुसार, डॉ. सगर अब अपने वर्तमान कार्यों के साथ-साथ महापौर परिषद सचिव की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। यह नियुक्ति मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69 (4) के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डॉ. सगर समय-समय पर शासन और निगम प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। आदेश के अंत में उल्लेख किया गया है कि यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस परिवर्तन की सूचना महापौर, अपर आयुक्त, समस्त विभाग प्रमुखों सहित संबंधित अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है।

इंदौर ने आगरा को भी सिखाया स्वच्छता का पाठ, इसके बाद वहां का रंग बदला

आगरा। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में आगरा ने देश में 10वीं रैंक हासिल की है। यह संभव हो पाया उस कूड़े के पहाड़ को हटाने की वजह से, जो शहर की खूबसूरती पर दाग लगा रहा था। इतना ही नहीं कूड़े की प्रोसेसिंग से कमाई भी की और रैंक भी सुधारी। एक साल में 85 वें स्थान से छलांग लगाकर देश के सबसे स्वच्छ 10 शहरों में आगरा शामिल हो गया। इसके पीछे बड़ी वजह कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के साथ ही इससे प्रोसेसिंग रही। इंदौर नगर निगम की तर्ज पर आगरा नगर निगम ने न केवल कचरे को निपटाया, बल्कि इससे कमाई भी की। स्वच्छ सर्वेक्षण में इस वजह से अच्छे अंक मिले, जिसका असर शहर की सफाई के साथ रैंकिंग पर पड़ा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आगरा नगर निगम हर दिन निकलने वाले 800 टन कचरे को वैज्ञानिक ढंग से निपटा कर कमाई भी कर रहा है।

मिशन के सह प्रभारी सुदेश यादव के मुताबिक हर दिन 500 टन गीला कचरा कंपोस्ट खाद बनाने में उपयोग हो रहा है। इससे 40 टन खाद हर दिन बनाई जा रही है। इसे कृभको खरीद रहा है और 3100 रुपये प्रति टन के हिसाब से भुगतान भी कर रहा है। नगर निगम के लिए यह गीला कचरा कमाई का बड़ा स्रोत है। इसके अलावा 100 टन गोबर से खाद बनाई जा रही है। करीब 10 टन कंपोस्ट खाद

इससे बनाई जा रही है, जो नगर निगम के पार्कों और सड़कों के किनारे लगे पौधों में उपयोग की जा रही है। इसका कुछ हिस्सा बेचा भी जा रहा है, जिसका 50त्न नगर निगम को मिल रहा है।

कूड़े से बिजली, अगले साल - कूड़े से बिजली बनाने का प्लांट सितंबर 2026 में चालू हो जाएगा। तब आगरा की रैंकिंग में और सुधार होगा। टॉप-3 में आने के लिए कूड़े से बिजली बनाने के साथ इन प्लांटों का पूरी क्षमता के साथ संचालन जरूरी है। नगर निगम ने कुबेरपुर लैंडफिल साइट पर 72 एकड़ जमीन में से 47 एकड़ कचरे को निपटाकर खाली कराई है। इसमें से 11 एकड़ पर हरियाली की गई है, वहीं 10 एकड़ पर मियावाकी पद्धति से जंगल विकसित किया जा रहा है। बाकी जमीन खाद बनाने, ब्लॉक बनाने, सेनेटरी लैंडफिल साइट बनाने में उपयोग की गई है।

कंपनियां खरीद रही प्लास्टिक दाने - स्वच्छ सर्वेक्षण में कूड़े के पहाड़ खत्म होने के साथ कचरा निस्तारण को देखा गया। सबसे बड़ी मुसीबत प्लास्टिक कचरे की थी, जिसे प्लास्टिक दाना बनाकर और शू लास्ट के साथ सिंचाई के लिए प्लास्टिक पाइप बनाने में उपयोग किया जा रहा है। हर दिन पांच टन प्लास्टिक प्रोसेसिंग की जा रही है, जबकि 65 टन मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में निकाली जा रही है। इससे नगर निगम को चार लाख रुपये की आय हो रही है। सुदेश यादव ने बताया कि भवन निर्माण के मलबे से पेवर, कर्व ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। 20 टन क्षमता वाले प्लांट की क्षमता अब बढ़ाकर 150 टन की जा रही है।

इंदौर से सीखें यह सबक

- घरों से गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग लेना।
- कूड़ा उठाने की डिजिटल मॉनिटरिंग, स्कैनिंग।
- कूड़ा उठाने वाले वाहनों की जीपीएस लोकेशन।
- कूड़े के पुराने पहाड़ों को प्रोसेसिंग के जरिये खत्म किया।
- रोजाना आने वाले कचरे की प्रोसेसिंग कर खाद बनाई।
- प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल सड़क, दाना बनाने में।
- शहर में सड़कों पर, गलियों में बने डलावघर खत्म किए।
- ट्रीटेड सीवर का इस्तेमाल पार्क के पौधों की सिंचाई में।
- घर-घर में अलग-अलग कचरे के लिए डस्टबिन दिए।

वन विभाग ने भी नागपंचमी मनाई 3 टीमों ने 32 सांप जंगल में छोड़े

कुछ सपेरों ने सांप की तस्वीर या नकली सांप की पूजा कराई

इंदौर। नागपंचमी के अवसर पर जहां एक ओर शहर में मंदिरों में पूजा-अर्चना और नागदेवता का विशेष श्रृंगार किया गया, वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने इस बार भी सक्रियता दिखाते हुए 32 सांपों को सपेरों से मुक्त कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। लोग भी परंपरा के अनुसार इन सांपों की पूजा करते दिखे। लेकिन, इस दौरान वन विभाग पूरी तरह सतर्क रहा और अलग-अलग इलाकों में टीमों ने निगरानी रखी। डीएफओ प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर इंदौर रेंज में तीन टीमें बनाई गई। इस बार भी कुछ स्थानों पर सांपों को पकड़कर उनकी पूजा के लिए कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थानों पर लाया जा रहा था। वन विभाग द्वारा बनाई गई तीन विशेष निगरानी टीमों ने समय रहते कार्रवाई कर वन्यजीवों को सुरक्षित किया।

रेंजर संगीता ठाकुर ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत की गई। क्योंकि, सांपों को बंदी बनाना और

जबरन दूध पिलाना अपराध है। रेंजर संगीता ठाकुर ने विजय नगर, भंवरकुआं और अन्नपूर्णा सहित आसपास के इलाकों में टीमों को नजर रखने को कहा गया। टीमें दिनभर गश्त करती रहीं। वन विभाग की टीमों ने 32 सांपों को सपेरों से छुड़ाया और उन्हें सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया गया। वन कर्मियों ने बताया कि ज्यादातर सपेरे

निगरानी में लगे तीन विशेष दल

दल-1 : नेतृत्व :आशाराम यादव, क्षेत्र- राजबाड़ा, विजय नगर, इंदौर शहर
दल-2 : नेतृत्व : कोमल पालीवाल, क्षेत्र- नवलखा, भंवरकुआं, रिंग रोड
दल-3 : नेतृत्व : सूर्यनारायण यादव, क्षेत्र- अन्नपूर्णा, लाबरिया भैरव
- प्रत्येक दल में वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक व आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए।

चोरल, महू और सांवेर जैसे ग्रामीण इलाकों से सांप पकड़ कर लाए थे। कुछ सपेरों ने यह भी कहा कि वे जंगलों से सांप लाए हैं। जब वन विभाग ने कार्रवाई की तो कुछ जगहों पर विवाद की स्थिति भी बनी, लेकिन सपेरों को समझाइश देकर छोड़ा गया। वहीं एक सामाजिक संस्था (एनजीओ) ने भी वन विभाग की मदद की। उन्होंने भी कई जगहों पर जाकर सांपों को छुड़वाया। वन विभाग ने नागरिकों से अपील की, कि यदि वे कहीं सांपों का अवैध प्रदर्शन देखें, तो तत्काल विभाग को सूचित करें।

बहनों के लिए रक्षाबंधन पर डाक विभाग की खास पहल

विशेष लेटर बॉक्स और गिफ्ट पैक की सुविधा शुरू

इंदौर। रक्षा-बंधन पर्व पर बहनों की भावनाओं को सम्मान देते हुए डाक विभाग ने इंदौर जीपीओ परिसर में विभिन्न शहरों के लिए अलग-अलग विशेष लेटर बॉक्स लगाए हैं। इसका शुभारंभ पोस्टमास्टर जनरल प्रीती अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के दौर में भी बहनों का डाक विभाग पर अटूट विश्वास कायम है। राखी के त्वरित और सुरक्षित वितरण हेतु भोपाल, जबलपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खंडवा, खरगोन और सेना के 56 एपीओ व 99 एपीओ के लिए विशेष लेटर बॉक्स की व्यवस्था की गई है। इस बार विभाग ने 111 रुपए में विशेष गिफ्ट बॉक्स भी उपलब्ध कराया है, जिसमें राखी, कुकीज, कुमकुम, अक्षत और स्पीड पोस्ट का शुल्क शामिल है। इंदौर जीपीओ में काउंटर नं. 8 को विशेष राखी बुकिंग काउंटर घोषित किया गया है। क्यूआर कोड के जरिए घर से भी राखी भेजने की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही 'सुकन्या रक्षा अभियान' के तहत 10 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाता भी खोला जा रहा है। कार्यक्रम में 5 बालिकाओं को पासबुक देकर सम्मानित किया गया।

अब ड्रोन से सफाई और ऐप से निगरानी

इंदौर। स्मार्ट सिटी ने स्वच्छता में नवाचार की नई मिसाल पेश की है। 'सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ' अभियान के तहत दो नवाचारों की शुरुआत की गई। पहला, हैंड वॉशिंग डिजिटल मॉनिटरिंग ऐप जिससे सफाई मित्रों के हाथ धोने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है। दूसरा, ड्रोन आधारित ब्रीडिंग साइट सर्वेक्षण, जिससे हाइराइज बिल्डिंग में जलभराव की पहचान कर वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम की जा रही है। जोन-9 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू इस पहल में एमआईसी सदस्य अश्विनी शुक्ला, पार्षद, निगम अधिकारी, एनजीओ प्रतिनिधि और सफाई कर्मचारी शामिल रहे। एमजी रोड क्षेत्र में सर्वे के बाद निगम ने तुरंत फॉगिंग व दवा छिड़काव कर कार्यवाही की।

नगर निगम जेल रोड पर 150 साल पुराना जर्जर मकान तोड़ा

इमली बाजार में भी खतरनाक भवन का हिस्सा हटाया

इंदौर। बारिश के मौसम में जर्जर मकानों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए नगर निगम सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में मंगलवार को जेल रोड स्थित एक करीब 150 साल पुराने तीन मंजिला जर्जर मकान के खतरनाक हिस्से को जेसीबी की मदद से कुछ ही मिनटों में ध्वस्त कर दिया गया। यह मकान झोन क्रमांक 3 के अंतर्गत आता है और इसके ऊपरी हिस्से को असुरक्षित मानते हुए कार्रवाई की गई। भवन अधिकारी अश्विन जनवदे ने बताया कि इस मकान के निचले हिस्से में किराएदार रह रहे थे जबकि ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था, जिसे

तत्काल हटाया गया। नगर निगम द्वारा जून में किए गए सर्वे में 92 मकान जर्जर घोषित किए गए थे, जिनमें अब तक लगभग 30 पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं, हाल ही में झोन 11 में एक साथ रिवर साइड क्षेत्र में 18 मकानों को हटाया गया था। इसी तरह आज इमली बाजार चौराहा क्षेत्र में राधेश्याम साहू के जर्जर मकान के खतरनाक हिस्से को भी हटाया गया। नगर निगम आयुक्त के निर्देशानुसार सभी भवन अधिकारियों और रिमूवल टीमों को समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पूरे प्रदेश में बारिश के मामले में इंदौर सबसे पीछे, 32 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई

अब तक 10.02 इंच बारिश, जबकि औसत 15 इंच होना चाहिए

इंदौर। बारिश के मामले में इस साल इंदौर जिला अपने आसपास के जिलों से काफी पीछे रह गया। प्रदेश के जिलों के बारिश के आंकड़े बताते हैं कि इंदौर इस कतार में सबसे पीछे है। इंदौर में अब तक सामान्य औसत से 32 प्रतिशत कम बारिश हुई। प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर सामान्य से दुगने से ज्यादा बारिश हो चुकी, लेकिन इंदौर अपनी सामान्य बारिश के लिए ही तरस रहा है। इंदौर के प्रदेश में सबसे पीछे रह जाने का खुलासा मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जारी की गई प्रदेश के सभी जिलों की रिपोर्ट में हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर जिले में अब तक 10.02 इंच बारिश हुई। जबकि, जिले में इस समय तक औसत 15 इंच बारिश हो जाना चाहिए थी। इस तरह इंदौर अपनी सामान्य बारिश से 4.8 इंच पीछे चल रहा है जो सामान्य से करीब 32% कम है। इसके साथ ही इंदौर प्रदेश का सामान्य बारिश की तुलना में सबसे पिछड़ा जिला भी बन चुका। इससे पहले सबसे नीचे शाजापुर का नाम था और इंदौर दूसरे स्थान पर था। लेकिन, सोमवार को इंदौर सबसे नीचे वाले स्थान पर आ गया। इंदौर के बाद सामान्य से 28% कम बारिश के साथ शाजापुर दूसरे स्थान पर है।

पूरे प्रदेश में 54% ज्यादा बारिश

भोपाल मौसम केंद्र द्वारा बारिश की रिपोर्ट 1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन के अंतर्गत 28 जुलाई तक के डेटा के आधार पर तैयार की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, तो यहां सामान्य से 54% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में जहां सामान्य से 66% ज्यादा बारिश हुई, वहीं पश्चिम मध्य प्रदेश में सामान्य से 44% ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई। रिपोर्ट में इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के सिर्फ 8 जिले हैं, जहां सामान्य से कम बारिश हुई। शेष प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई। जिसके कारण प्रदेश का कुल औसत सामान्य से आगे है।

अच्छी बारिश की उम्मीद नहीं- सोमवार रात से शुरू हुई बारिश मंगलवार को भी जारी रही। शहर में अच्छी बारिश की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक इंदौर में हल्की बारिश ही देखने को मिलने की संभावना है। आने वाले कुछ दिनों में भी इंदौर अपने सामान्य कोटे 36-38 इंच तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर इंदौर से बादलों की यह बेरुखी आगे भी जारी रही, तो शहर सामान्य बारिश से आगे बढ़ सकता है।

रात से सुबह तक हल्की बूंदाबांदी

विमानतल स्थित मौसम केंद्र के मुताबिक मंगलवार रात से बुधवार सुबह के बीच शहर में रुक रुककर हल्की बारिश देखने को मिली। इस दौरान कल 4.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं दिन का अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री और कल की अपेक्षा 1.4 डिग्री कम था। रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा जो सामान्य से एक डिग्री अधिक था। इस तरह दिन का अधिकतम और रात की न्यूनतम तापमान में सिर्फ 2.4 डिग्री का ही अंतर रहा।

संपादकीय

ऑपरेशन सिंदूर : कुछ जवाब बाकी

कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा चलाए ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के दोनों सदनों में करीब 32 घंटे चली चर्चा का लुब्बो लुआब केवल इतना है कि इस गंभीर मुद्दे पर सार्थक चर्चा कम, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हुए। विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों ने एक-दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की ज्यादा कोशिश की और सारी बहस मानो मोदी विरोध और मोदी बचाव में तब्दील हो गई। हालांकि इस बहस का जवाब देते हुए मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई सवालों के उत्तर स्पष्ट रूप से अथवा संकेतों में दिए, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल जिन्हें भ्रम भी कहा जा सकता है, और जो जनता के मन में तैर रहे हैं, उनके उत्तर अभी भी बाकी हैं। कब मिलेंगे, कोई नहीं जानता। जैसे कि क्या पाकिस्तान के साथ युद्धविराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ था या नहीं? सीमित युद्ध में भारत को कितना नुकसान हुआ, हुआ या नहीं और क्या युद्ध के दौरान भारत से कोई रणनीतिक गलती हुई, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सैन्याधिकारियों ने बाहर दिए बयानों में कहा है? हालांकि प्रधानमंत्री ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस पर तीखे हमले करते हुए उस पर मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होते जाने का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि सिंधु जल समझौते जैसी गलती नेहरूजी ने की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करीब दो घंटे चले भाषण में अलबत्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीज़फ़ायर को लेकर 'मध्यस्थता' वाले दावे को सिरे से ख़ारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न अब करेगा। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जरूर तीन चार बार फोन कर दबाव बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से नहीं किया कि युद्धविराम में डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोहरा चुके हैं कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में भूमिका निभाई थी। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रंप के सीज़फ़ायर के दावों को लेकर मोदी सरकार को घेरा था और संसद में इस पर बयान देने की चुनौती दी थी। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने 29 बार सीज़फ़ायर कराने का श्रेय लिया। अगर वे झूठ बोल रहे हैं, तो अगर पीएम मोदी में इंदिरा गांधी का 50 प्रतिशत भी साहस है, तो वे कहें कि ऐसा नहीं था। यही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसी महीने दावा किया था कि हाल के भारत पाक संघर्ष में पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे? हालांकि भारत कह चुका है कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया में भारत के समर्थन पर ज्यादातर देशों की 'चुप्पी' की व्याख्या पीएम मोदी ने भारत की कार्रवाई के समर्थन के रूप में की। जबकि पाकिस्तान के साथ तीन देश खुलकर साथ आए। बहस के दौरान एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी ने वाजिब सवाल उठाया कि जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त रुख अपनाया था, तो अब क्रिकेट के एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ़ कैसे खेलेगी? इसका कोई संतोषजनक जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है। ध्यान रहे कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) द्वारा जारी एशिया कप 2025 का शेड्यूल के अनुसार भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच पहला मुक़ाबला 14 सितंबर को है। लेकिन जब ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते तो स्पोर्ट्स और टेरर साथ कैसे चल सकते हैं?

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों से किसे फायदा?

नजरिया

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने
लेखक विदेश मामलों के जानकार हैं।

बांग्लादेश में तकरीबन पौने दो करोड़ हिन्दू रह रहे हैं और इन्हें देश के सम्पूर्ण इस्लामीकरण में कट्टरपंथियों द्वारा बड़ी बाधा समझा जा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और पाकिस्तान के हस्तक्षेप के चलते इस्लामिक कट्टरतावाद को बढ़ावा मिला है। बांग्लादेश का हालिया घटनाक्रम इसी का उदहारण है,जहां कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त करते हुए कट्टरपंथी लगातार हिन्दुओं को निशाना बनाया गया है। कुख्यात इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव मजबूत करने में दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश उसका खास मददगार हो सकता है। 2015 में शियाओं के जुलूस और विदेशी नागरिकों पर ढाका में जो हमले हुए थे उसमें इस्लामिक स्टेट का हाथ सामने आने की बात सामने आई थी।

बांग्लादेश के रंगपुर ज़िले में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ़ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के आरोप में कई हिंदू परिवारों के घरों को निशाना बनाया गया। घटना के बाद कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। ऐसे तथ्य सामने आएं है जिसके अनुसार मस्जिद के लाउडस्पीकर से लोगों को हमले के लिए उकसाया गया। इस घटना के बाद इलाके के हिंदू परिवारों में दहशत है और कई लोग पलायन कर चुके हैं। प्रशासन कड़ी कार्रवाई का दावा कर रहा है लेकिन कट्टरपंथी समूहों के व्यापक दबाव के चलते हमलावरों पर शायद ही कोई कार्यवाही हो।

इस समय बांग्लादेश में तकरीबन पौने दो करोड़ हिन्दू रह रहे है और इन्हें देश के सम्पूर्ण इस्लामीकरण में कट्टरपंथियों द्वारा बड़ी बाधा समझा जा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव और पाकिस्तान के हस्तक्षेप के चलते इस्लामिक कट्टरतावाद को बढ़ावा मिला है। बांग्लादेश का हालिया घटनाक्रम इसी का उदहारण है,जहां कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्वस्त करते हुए कट्टरपंथी लगातार हिन्दुओं को निशाना बनाया गया है। कुख्यात इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस के द्वारा यह विश्वास किया जाता है कि दक्षिण एशिया में उसका प्रभाव मजबूत करने में दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश बांग्लादेश उसका खास मददगार हो सकता है। 2015 में शियाओं के जुलूस और विदेशी नागरिकों पर ढाका में जो हमले हुए थे उसमें इस्लामिक स्टेट का हाथ सामने आने की बात सामने आई थी।

हालांकि बंगाल में साम्प्रदायिकता का इतिहास बहुत पुराना है जो बंगलादेश में अक्सर प्रतिबिम्बित होता है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी नोआखाली के जिक्र के बिना अधूरी मानी जाती है। तकरीबन पचहत्तर साल पहले 1946 में लक्ष्मी पूजन के दिन यहां भीषण साम्प्रदायिक दंगे शुरू हुए थे। उस समय जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे से सबसे ज्यादा प्रभावित इस क्षेत्र में हजारों हिन्दुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। सात दशक से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद दुनिया में बहुत कुछ बदला है लेकिन मौजूदा बांग्लादेश के चटगांव डिवीज़न के नोआखाली ज़िले में स्थितियां जस की तस नजर आती है। 2021 में दुर्गा पूजा पर नोआखाली में एक बार फिर हिन्दुओं को बड़े पैमाने निशाना बनाया गया। 1946 में नोआखाली मुस्लिम बहुल था,लेकिन ज़मींदारों में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। उस समय यह माना गया था कि नोआखाली में एक सुनियोजित दंगा था,जिसका लक्ष्य हिंदुओं को भगाकर उनकी संपत्तियों पर क़ब्ज़ा करना था। इस समय भी हालात मिले जुले और समान नजर आते है।

दुर्गा पूजा पर हिन्दुओं और उनके धर्म स्थलों पर हमले इतने सुनियोजित थे कि पुलिस प्रशासन और सरकार के नुमाइन्दें प्रभावित हिन्दुओं को राहत देने में नाकामयाब रहे। यहां तक की अल्पसंख्यक हिन्दुओं का यह कहना है कि प्रशासन से सुरक्षा के लिए मदद की गुहार करने के बाद भी उसे नजरअंदाज कर दिया गया। 1946 में महात्मा गांधी दिल्ली से पंद्रह सौ किलोमीटर दूर सांप्रदायिकता की आग में जल रहे पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में अमन बहाली की कोशिशों में जुटे थे और उन्होंने नोआखाली में लम्बा समय

बिताया था,इस दौरान उनके साथ जेबी कृपलानी,सुचेता कृपलानी,राममनोहर लोहिया और सरोजनी नायडू जैसे नेता था जिनकी अमन बहाली की कोशिशे कामयाब रही थी। लेकिन इस समय मौजूदा सरकार के नुमाइन्दें ऐसी कोई कोशिश करते नहीं दिख रहे है और इसी का परिणाम है कि नोआखाली समेत जेसोर,देबीगंज,राजशाही,मोईदनारहाट , शांतिपुर,प्रोधनपारा,आलमनगर,खुलना,राजशाही,रंगपुर और चटगांव जैसे अहम इलाकों से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए है। यह पलायन का तात्कालिक कारण जरुर है लेकिन पीछे बांग्लादेश में पनपने वाला वह कट्टरतावाद है जिसके परिणामस्वरूप अगले कुछ सालों में इस देश के हिन्दू विहीन ह ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ.अबुल बरकत का एक शोध 2016 में सामने आया था जिसके अनुसार यह दावा किया गया है कि करीब तीन दशक में बांग्लादेश से हिंदुओं का नामोनिशान मिट जाएगा। इस शोध के मुताबिक हर दिन अल्पसंख्यक समुदाय के औसतन 632 लोग बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं। देश छोड़ने की यह दर बीते 49 सालों से चल रहा है और यदि यही दर आगे भी जारी रही तो अगले तीस वर्षों में देश से करीब-करीब सभी हिंदू चले जाएंगे।

यह भी बेहद दिलचस्प है कि बंगलादेश के मुक्ति संग्राम में हिन्दुओं ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था और इसी के कारण 1971 में पूर्वी पाकिस्तान कहे जाने वाले और मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी। उस समय यह माना गया था कि बांग्लादेश भारत की तरह ही समावेशी विचारों वाला लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य होगा। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद स्थितियां तेजी से बदल गई। बाद के शासकों जिया-उर-रहमान और जनरल एच.एम. इरशाद के सैन्य शासनकाल में देश का इस्लामीकरण तेजी से हुआ। खालिदा जिया जैसी नेताओं ने जमात-ए -इस्लामी जैसे संगठनों को मजबूती दी और इसी कारण बांग्लादेशी समाज में कट्टरता को बढ़ावा मिला। इसके सबसे ज्यादा घातक नतीजे यहां रहने वाले हिन्दुओं को भोगने को मजबूर होना पड़ा है।

अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े है। इसके पहले पिछले कुछ वर्षों से बांग्लादेश में अवामी लीग का शासन था और प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिन्दू अल्पसंख्यकों के लिए उदार माना जाता था। लेकिन इसके बाद भी वे अल्पसंख्यकों के लिए कोई निर्णायक बदलाव लाने में असफल रही। खासकर सम्पत्ति नियमों को लेकर। गौरतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिन्दुओं के पलायन का प्रमुख कारण सम्पत्ति रही है जिस पर कब्जा करने के लिए कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा अक्सर और सुनियोजित रूप से उन्हें निशाना बनाया जाता है।1965 में तत्कालीन पाकिस्तान सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम बनाया था,जिसे अब वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत के साथ जंग में हुई हार के बाद अमल में लाए गए इस क़ानून के तहत 1947 में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से भारत गए लोगों की अचल संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। बांग्लादेश में शत्रु संपत्ति अधिनियम की वजह से लाखों हिंदुओं को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी थी। प्रो.अबुल बरकत के अनुसार,वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट की वजह से बांग्लादेश में 1965 से 2006 के दौरान अल मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे तब भी उनकी यात्रा का विरोध बड़े पैमाने पर हुआ था और इसमें जमात-ए-इस्लामी की भूमिका खास मानी जाती है। देश में प्रतिबन्ध लगने के बाद यह अन्य कट्टरपंथी ताकतों को मजबूत करने में जुटा है और इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहा है। 2010 में जमात-ए-इस्लामी समर्थित संगठन हिफाज़त-ए-इस्लाम ने बांग्लादेश में महिलाओं की शिक्षा का विरोध बड़े पैमाने पर किया था। इस समय ईशनिंदा की अफवाह फैलाकर अल्पसंख्यक हिन्दुओं को बांग्लादेश से भागने को मजबूर करने की सुनियोजित साजिश को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया जा रहा है और इसमें सबसे बड़ा मददगार बांग्लादेश का प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन जमात-ए-इस्लामी है। यह दल बांग्लादेश में इस्लामी शासन स्थापित करना चाहता है,इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिमायती माना जाता है। यहां तक की 1971 में जब बांग्लादेशी जब पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों का सामना कर रहे थे तब भी यह दल पाकिस्तान का समर्थन ले रहा था। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्ज़े का भी इस संगठन ने समर्थन किया था और अब यह पाकिस्तान में पुनः बंगलादेश के विलय के पक्ष में भी माहौल बनाने में जुटा ।

वैश्विक सुस्ती के बीच स्थिर विकास की ओर भारत

आर्थिकी

ममता कुशवाहा
लेखक शिक्षिका हैं।

विकास की राह में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था झुकी हुई हो, व्यापारिक नीतियाँ डगमगाने लगें, और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ते जाएँ, तब किसी देश का आर्थिक रूप से 'स्थिर? रहना मात्र एक आँकड़ा नहीं, बल्कि उसकी नीतिगत परिपक्वता, आंतरिक सामर्थ्य और व्यापक सामाजिक-संस्थागत दृढ़ता का प्रतीक होता है। आज जब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि के अनुमानों में कटौती की है, ऐसे समय में भारत का आर्थिक रूप से स्थिर बने रहना न केवल एक उपलब्धि है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का द्वार भी खोलता है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी गति बनाए रखने का संकेत दे रही है, वह न केवल इसके आर्थिक ढाँचे की लचीलापन को दर्शाता है, बल्कि इसके नीति-निर्धारकों की दूरदर्शिता की भी पुष्टि करता है। परंतु यह स्थिरता कोई संयोग नहीं है, बल्कि बहुस्तरीय प्रयासों, विश्लेषणों और सूक्ष्म संतुलनों का परिणाम है।

विश्व बैंक औरआईएमएफ दोनों ने अपने हालिया पूर्वानुमानों में वैश्विक वृद्धि दर को नीचे गिरा दिया है। आईएमएफ ने जहाँ 2025 के लिए वैश्विक विकास दर मात्र 2.8 प्रतिशत आँकी है, वहीं विश्व बैंक का अनुमान और भी निम्न 2.3 प्रतिशत पर है। इन अनुमानों में कटौती का कारण वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, भूराजनीतिक तनाव (विशेषकर रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-गाजा संघर्ष, चीन-अमेरिका तनाव आदि), आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएँ और संरक्षणवादी व्यापार नीतियाँ हैं। ऐसे वैश्विक संकट के वातावरण में भारत की अनुमानित 6.5 प्रतिशत वृद्धि दर न केवल उल्लेखनीय है, बल्कि यह इंगित करती है कि भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था में संतुलन और गतिशीलता विद्यमान है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आर्थिक स्थिति रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय की मासिक समीक्षा इस बात की पुष्टि करती है कि भारत की आर्थिक गतिविधियाँ लचीली बनी हुई हैं। इस लचीलापन के कई कारण हैं। सबसे पहले, कृषि क्षेत्र की स्थिति संतोषजनक रही है। खरीफ बुवाई के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल रही हैं, जिससे ग्रामीण मांग को मजबूती मिली है। साथ ही, रबी की अच्छी फसल और सकारात्मक मानसूनी पूर्वानुमान ने ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति को भी सशक्त किया है।

औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता उपयोग का स्तर लंबे समय के औसत से ऊपर बना हुआ है, जिससे यह संकेत मिलता है कि उद्योगों में निवेश और उत्पादन दोनों सक्रिय हैं। इसके अलावा, ई-वे बिल, टोल कलेक्शन और डिजिटल पेमेंट्स जैसे उच्च-आवृत्ति संकेतक मजबूत आर्थिक गतिविधियों का परिचायक हैं। डिजिटल इकोनॉमी का सतत विस्तार, औपचारिकरण की प्रक्रिया और आधारभूत संरचना में सरकारी निवेश ने अर्थव्यवस्था को झटकों से उबरने की शक्ति प्रदान की है।

जहाँ एक ओर कुछ संकेतकों ने आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों में गिरावट के संकेत भी स्पष्ट हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) अप्रैल में केवल 2.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि आठ कोर सेक्टर जैसे कोयला, स्टील, सीमेंट आदि ने अप्रैल-मई में मात्र 0.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई। ICRA की रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन, टू-व्हीलर उत्पादन, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक और घरेलू एयरलाइन यातायात जैसे आठ मुख्य संकेतकों में भी गिरावट दर्ज की गई है। शहरी मांग में भी नरमी के संकेत मिले हैं, जिसका प्रभाव निर्माण क्षेत्र और वाहन बिक्री जैसे क्षेत्रों में देखा गया है।

निर्यात क्षेत्र में भी चिंता के संकेत हैं। वस्तु निर्यात में इस वर्ष अब तक मात्र 3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, जो अत्यंत सीमित है। यदि पेट्रोलियम उत्पादों को हटाया जाए, तो स्थिति थोड़ी बेहतर होती है, किंतु फिर भी यह वैश्विक माँग की कमजोरी और व्यापारिक अनिश्चितताओं का प्रतिबिंब है। IMF के अनुसार वैश्विक व्यापार वृद्धि 2025 में मात्र 1.7 प्रतिशत रहने की संभावना है, जो पहले के 3.2 प्रतिशत अनुमान से 1.5 प्रतिशत अंक कम है। यह वैश्विक व्यापारिक मंदी भारत जैसे निर्यातक देश के लिए चिंता का विषय है, विशेषतः तब जब सेवा क्षेत्र और उच्च तकनीकी उत्पादों पर वैश्विक निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

इन विरोधाभासी संकेतों के बीच भारत के नीति-निर्माताओं की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे घरेलू मांग को बनाए रखते हुए बाहरी जोखिमों का प्रभाव न्यूनतम करें। वित्त मंत्रालय का यह स्वीकारना कि 'बाहरी चुनौतियाँ भारत की विकास यात्रा को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती हैं।' इस बात की गंभीर चेतावनी है कि यदि स्थिति का कुशलता से प्रबंधन नहीं किया गया, तो यह स्थिर विकास पथ बाधित हो सकता है। इसके लिए सरकार को कई मोर्चों पर सक्रिय रहना होगा, बुनियादी ढाँचे में निवेश को गति देना, MSME क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, बैंकिंग प्रणाली में तरलता बनाए रखना, रोजगार निर्माण को प्राथमिकता देना और डिजिटल तथा हरित अर्थव्यवस्था को सशक्त करना। इसके साथ ही, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए व्यापार समझौतों का पुनरावलोकन, वैश्विक साझेदारियों का विस्तार और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं को तेज़ी से लागू करना आवश्यक होगा।

वर्तमान संदर्भ में कृषि, सेवा और निर्माण, ये तीन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकते हैं। कृषि क्षेत्र में अनुकूल मानसून और फसल उत्पादन की स्थिरता ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया है। सेवा क्षेत्र, विशेषतः IT, फिनटेक और स्वास्थ्य सेवा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत को आगे रख रहे हैं। वहीं, निर्माण क्षेत्र जिसमें सड़क, रेलवे, आवास, बिजली जैसे बुनियादी ढाँचे शामिल हैं, न केवल रोजगार सृजन का बड़ा स्रोत है, बल्कि इसके जरिए निवेश और उपभोग का चक्र भी गति पाता है। यदि सरकार इन तीनों क्षेत्रों को एक समेकित नीति के तहत विकसित करती है, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर एक स्थिर और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।

वास्तव में आज भारत एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, जहाँ एक ओर वैश्विक सुस्ती और अनिश्चितताएँ हैं, तो दूसरी ओर आंतरिक आर्थिक शक्ति, उपभोग क्षमता और नीति-निर्माण की स्थिरता है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय की रिपोर्टें जहाँ अवसरों और उपलब्धियों की ओर इशारा करती हैं, वहीं वे यह भी संकेत देती हैं कि सावधानी, सूझबूझ और दूरदर्शिता के बिना यह विकासगाथा अस्थायी साबित हो सकती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत केवल 'होल्डिंग स्टेडी' न रहे, बल्कि 'फॉर्जिंग अहेड' की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। इसके लिए आवश्यक होगा कि हम अपने आर्थिक संकेतकों की गहराई से निगरानी करें, समय रहते नीति-सुधार लाएँ और सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर भी समावेशिता को बढ़ावा दें। तभी भारत न केवल वैश्विक संकटों के बीच खड़ा रह सकेगा, बल्कि उन्हें अवसरों में बदलने की सामर्थ्य भी अर्जित कर सकेगा।

स्कूल भवनों का ढहना प्राकृतिक दुर्घटना नहीं

दृष्टिकोण

ब्रजेश कानूनगो
लेखक स्तंभकार हैं।

शिक्षण संस्थाओं में होने वाली दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या है, जिसमें कई बार जान-माल की क्षति भी हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं भी एक कारण होती हैं जिनसे हादसे हो जाते हैं। भारी बारिश या बाढ़ के कारण शिक्षण संस्थाओं को बंद करना पड़ता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जुलाई 2025 में हरियाणा में भारी बारिश के कारणजिला प्रशासन ने दो दिन के लिए शिक्षण संस्थाओं को बंद रखने का निर्देश दिया था। अन्य राज्यों में भी भारी बारिश या कड़ाके की ठंड के दौरान सावधानी के तौर पर स्कूलों की छुट्टियां घोषित की जाती रही हैं। भूकंप जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी शिक्षण संस्थाओं के लिए खतरनाक हो सकती हैं। इन आपदाओं से निपटने के लिए उन क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा उपायों का होना तब बहुत आवश्यक हो जाता है।

इनसे हटकर भी विद्यार्थियों का जीवन कुछ कारणों से संकट में पड़ जाता है, मसलन स्कूल बसों या कॉलेज वाहनों से जुड़ी सड़क दुर्घटनाएं एक आम समस्या होती गई है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों की नियमित जांच और ड्राइवरों के प्रशिक्षण की आवश्यकता सुनिश्चित की जाने के उपाय आदि किए जाते हैं बावजूद इसके घटनाएं जारी रहती आई हैं। भवन में आग लगने, बिजली के झटके आदि या इस तरह की अन्य घटनाएं भी सुनने को मिलती रहती हैं। इन घटनाओं से निपटने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन योजनाओं की व्यवस्था करने की कोशिश कितनी की जाती है, यह भी देखा जाना जरूरी है।

ऐसी दुर्घटनाओं से बचाव के लिए प्रायः सीसीटीवी कैमरे लगाना, सुरक्षा गार्ड तैनात करना, और आपातकालीन निकास मार्गों की व्यवस्था की जाती है। छात्रों, शिक्षकों, और कर्मचारियों को सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक और प्रशिक्षण देना आवश्यक है। स्कूलों और कॉलेजों के भवनों और उपकरणों की नियमित जांच होती रहे तो दुर्घटनाओं को रोका या कम अवश्य किया जा सकता है। किन्तु हाल ही की कुछ खबरें हमे चौंकाती ही नहीं बल्कि व्यथित कर देती हैं। सबसे बढ़कर स्कूल भवनों के जर्जर हिस्सों के गिर जाने की घटनाएं बहुत दुखद और चिंताजनक हैं।

स्कूल भवनों के जर्जर होते जाने के पीछे कई कारण नजर आते हैं। उनके रखरखाव और पुराने भवनों की उचित मरम्मत का अभाव भी दिखाई देता है। आवश्यक धन राशि का समय पर उपलब्ध नहीं होना या प्राप्त हो जाने पर उसका मरम्मत कार्य पर खर्च न होकर अन्य सुविधाओं में उपयोग कर लेना भी भवनों की मरम्मत में विलंब का कारण हो जाता है। इस राशि के खर्च में भ्रष्टाचार की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता, घटिया निर्माण भी दुर्घटना की एक परोक्ष वजह बन जाता है। अंततः इन सब अनियमितताओं और लापरवाही का नतीजा जन धन हानि के रूप में दिखाई देता है। बच्चों और शिक्षकों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ जाती है या गंभीर रूप से वे घायल हो जाते हैं।

जुलाई 2025 में झालावाड़ के पीपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई और 30 से अधिक बच्चे घायल हुए। यद्यपि इस हादसे के बाद प्रशासन ने 5 शिक्षकों को निलंबित कर दिया और राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों की जर्जर इमारतों की जांच शुरू कर दी गई है। क्या इन सब से उन पालकों के हृदय पर उभरे दुख के पहाड़ का वजन कम हो जाएगा? उनकी आंखों के आंसू थम जाएंगे। जिन मां बाप ने अपने और बच्चों को लेकर सुखमय सपने देखे होंगे, उन पर तो जैसे वज्रपात ही हो गया होगा, उनका क्या होगा?

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जुलाई 2024 में दिल्ली के दरियागंज में एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा था। शुक्र है इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन यह घटना स्कूलों की सुरक्षा को लेकर चिंता तो बढ़ाती ही है। उत्तराखंड में सितंबर 2022 में चम्पावत जिले के मौनकांडा स्कूल में शौचालय की छत गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर के जर्जर स्कूल भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। राजस्थान में झालावाड़ के सरकारी स्कूल की छत गिरने की घटना के तुरंत बाद एक सप्ताह के भीतर जैसलमेर के पूनमनगर गांव के स्कूल गेट का पीलर गिरने से एक सात वर्षीय छात्र की मौत और एक शिक्षक के घायल होने का समाचार पुनः स्तब्ध कर देता है। बताया जाता है नागौर और सिरोही में भी ऐसी ही घटनाएं प्रकाश में आई हैं। एक सूचना के अनुसार राज्य में 2256 स्कूल और एक हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हालत में हैं।

यह पढ़कर तब हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है जब जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति बच्चों की मौत पर कहते हैं कि, स्कूल की मरम्मत कार्य एक सरकारी प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता है। यह कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से पैसे निकालकर दे दें।

जिम्मेदारों के ऐसे असंवेदनशील बयानों से यही धारणा और आशंका बलवती होती है कि छात्रों की शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं की सुरक्षा को लेकर हम कितने गंभीर होकर सोच पाते हैं। विचार कीजिए!

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

दिल सैंयारा हो गया

हास्य व्यंग्य

सुरेश सौरभ
लेखक व्यंग्यकार हैं।

जब मदारी हमारे गांव में तमाशा दिखाने आता था, तो उसके साथ में एक नटखट छोकरा भी होता था। जिसे लोग जमूरा-जमूरा कह कर पुकारते थे। जब मदारी अपना खेल-तमाशा शुरू करता, तब वह जमूरा, कभी हंसता, कभी रोता चिल्लाता, कभी गाता-गुनगुनाता। तमाम मसखरी के अनोखे करतब करता हुआ, वह लोगों का भरपूर मनोरंजन करता था। तब बड़ा मजा आता था। मदारी और जमूरे का वह अनूठा करिश्माई करतब देखकर, सब हैरत में पड जाते थे।साहेबान, मेहरबान, कद्रदान आइए हमारे पास, दिखाते हैं, अभी आपको बंगाल का मशहूर काला जादू... बनाते हैं, इस छड़ी को अभी सांप और लाते हैं, अभी आगरे का फेमस यहां ताज, गिली-गिली अप-अप...ऐसे कई जुमले कई दिनों तक दिलोदिमाग पर नाचते रहते थे। मदारी के बिना इशारे इतने अनोखे दिलचस्प करतब जमूरा कैसे कर पाता है, यह हम कतई जान न पाते थे, पर जब थोड़ा बड़ा हुआ-तब बड़े लोगों ने हमें बताया कि सब माया का खेला होता है, जमूरे और मदारी के फिक्स बिजनेस का यह सब रेला होता है। सैंयारा फिल्म देखने के बाद थियेटर के बाहर और अंदर जिस तरह के इमोशनल करतब, लड़के-लड़कियां दिखा हैं, मुझे तो बरबस उस जमूरे की याद आ रही है, जो कभी अपनी शर्ट उतार कर बेहद भावुक होकर आँसू बहाते हुए, नाचता था, गाता था।

चिल्लाता था। वह जमाना भी क्या, मनोरंजन का मजेदार जमाना था। अब सयाने लोग तो सैंयारा का पूरा मामला जमूरे और मदारी वाले उसी मैच फिक्सिंग का बता रहे हैं, कैसे कोई रोयेगा, कैसे कोई गायेगा, किस एंगल्स से कहां कौन जमूरा अधनंगा होकर दहाड़ेगा, चिल्लाएगा, मदारी ने पहले से ही यह सब फिक्स करके रखा है। और वह मदारी है, महोदय माया का। तगड़ी मार्केटिंग का। पेड मीडिया-सोशल मीडिया का। अब इन जमूरों की देखा-देखी कुछ नादान, ब्रेकअप से चोटिल-घायल हो चुके दिल भी फुदकने-मचलने लगे हैं,और मजे लेने वाले, दांत चियारते हुए उनकी रील बनाने लगे, सैंयारा सैंयारा जमूरे सा वह भी फालतू में गाने लगे।

विकसित देशों के युवा नयी-नयी खोज कर रहे हैं, नये-नये अविष्कार करके अपने देश को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे यहां के युवा चंद जूमरो और मदारियों चक्कर में आकर घनचक्कर बनकर लवेरिया का राग अलाप रहे हैं। कहते हैं, जिधर जवानी चलती है, उधर जमाना चलता है, हमारे यहां के अगर तमाम जवान लड़के-लड़कियों का दिल सैंयारा-सैंयारा हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि देश में टूटे दिलों को जोड़ने के लिये, उनकी संवेदनाओं को संजोने के लिए सरकार को एक राष्ट्रीय आयोग बनाना चाहिए, रोजगार अशिक्षा, भ्रष्टाचार, सामाजिक भेदभाव से बड़ी, अगर कोई समस्या है तो वह हमारे यहां चोट खाए टूटे तड़पते दिलों की ही है।

पुण्यतिथि पर विशेष

रमेश रंजन त्रिपाठी

लेखक स्तंभकार हैं।

आवाज के जादूगर मोहम्मद रफी

'जंगली' का तेज तर्रार याहू सॉन्ग हो, 'मधुबन में राधिका नाचे रे' जैसा क्लासिकल 'कोहिनूर' हो, 'मन तड़पत हरि दर्शन को आज' जैसी भक्त 'बैजू बावरा' की करुण पुकार हो, 'लाल किला' के अंतिम मुग़ल बादशाह की 'न किसी की आँख का नूर हूँ' जैसी बेबसी हो, 'मुग़ल-ए-आज़म' के सामने 'मोहब्बत ज़िंदाबाद' का उद्घोष हो, 'काला पानी' में 'हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए' का बेसुधपन हो, 'दुलारी' के विरह में 'सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे' की तड़प हो, 'जब प्यार किसी से होता है' में 'जिया हो जिया कुछ बोल दो' की उतावली हो, 'कर चले हम फिदा जाँ औ' तन साथियों' में देशभक्ति की 'हकीकत' हो, भावनाओं के सारे रंगों को जैसामोहम्मद रफी बयां करते थे, और कौन कर पाया है?

सन् 1958 की फिल्म 'देवर भाभी' में चरित्र अभिनेता राधाकिशन पर फ़िल्माया गया गीत 'मैके से आ जा बीवी रे' को सुनें। आपको यकीन नहीं होगा कि गाना खुद राधाकिशन ने नहीं, मोहम्मद रफी ने गाया है। रफी साहब को यह कमाल हासिल था कि वे कलाकार के व्यक्तित्व के अनुरूप अपनी आवाज में प्रभाव पैदा कर लेते थे। 'प्यासा' में चम्पी गीत 'सर जो तेरा चकराए' लगता है न कि इसे जॉनी वॉकर ही गा रहे हैं? शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद, धर्मेंद्र, विश्वजीत, महमूद और न जाने कितने कलाकारों के लिए पार्श्वगायन करते हुए वे जैसे खुद उस अभिनेता को अपनी आवाज में जीने लगते थे। इसके लिए वे गाने से पहले सिचुएशन और किस कलाकार पर गाना फ़िल्माया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी लिया करते थे। अनेक अभिनेता खुद पर फ़िल्माए जानेवाले रफी साहब के गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान मौजूद रहते थे।

मोहम्मद रफी के स्वर में दिव्यता और पवित्रता थी। शास्त्रीय संगीत की शिक्षा और कठोर रियाज़ ने उनकी गायकी को सौ टंच सोने के समान चमका दिया था। जैसे शुद्ध कंचन को किसी भी ढाँचे में ढालकर आभूषण का स्वरूप दिया जा सकता है, उसी तरह रफी साहब अपने निर्दोष और कुशल गायन से किसी भी गीत को अमर बना देते थे। 'जंगली' का तेज तर्रार याहू सॉन्ग हो, 'मधुबन में राधिका नाचे रे' जैसा क्लासिकल 'कोहिनूर' हो, 'मन तड़पत हरि दर्शन को आज' जैसी भक्त 'बैजू बावरा' की करुण पुकार हो, 'लाल किला' के अंतिम मुग़ल बादशाह की 'न किसी की आँख का नूर हूँ' जैसी बेबसी हो, 'मुग़ल-ए-आज़म' के सामने 'मोहब्बत ज़िंदाबाद' का उद्घोष हो, 'काला पानी' में 'हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए' का बेसुधपन हो, 'दुलारी' के विरह में 'सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे' की तड़प हो, 'जब प्यार किसी से होता है' में 'जिया हो जिया कुछ बोल दो' की उतावली हो, 'कर चले हम फिदा जाँ औ' तन साथियों' में देशभक्ति की 'हकीकत' हो, भावनाओं के सारे रंगों को जैसा मोहम्मद रफी बयां करते थे, और कौन कर पाया है? सीमित विधाओं या रस में निष्णात अनेक गायक होते हैं लेकिन सभी मूड के नग़मों को समान अधिकार से गाने की विशेषता मोहम्मद रफी में थी। अनेक हिंदी फ़िल्मों के क्लाइमेक्स में ट्विस्ट केवल रफी साहब की गायकी के कारण दर्शकों के मन को छू सका। कुछ उदाहरण देखिए- 'भीगी रात' में रफी साहब का गाया 'दिल जो न कह सका, वही राज-ए-दिल कहने की रात आई'।

फिल्म के अंत की जान यही गीत है। इस गाने को लता जी ने भी गाया है लेकिन असरदार तरीके से कहानी को मोड़ देनेवाला वर्जन तो रफी साहब ने गाया है। 'ग़ज़ल' में सुनील दत्त पर फ़िल्माया 'रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ' ही फ़िल्म का टर्निंग प्वाइंट है। 'जब जब फूल खिले' के आखिरी दृश्यों में हीरोइन के हृदय परिवर्तन को जैसा जस्टिफ़ाई 'यहाँ मैं अजनबी हूँ' गाने ने किया है, संवाद शायद ही कर पाते। दिग्गज फ़िल्मकार गुरुदत्त की दो महान फ़िल्मों, 'प्यासा' और 'काग़ज़ के फूल' के क्लाइमेक्स की कल्पना रफी साहब के गीतों के बगैर की जा सकती है भला? 'प्यासा' की खुश्क बेचैनी का वर्णन 'ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है' गीत के माध्यम से रफी साहब के स्वर के अलावा कौन कर पाता? 'काग़ज़ के फूल' की निरर्थकता 'देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी' लिखते हुए कैफी आजमी ने जिस असर को पैदा करने की कल्पना की थी, उसे मोहम्मद रफी ने साकार कर दिया। मोहम्मद

रफी की सक्रियता के वर्षों में उस समय के सभी बड़े छोटे सितारों ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उनकी आवाज का सहारा लिया था। लता मंगेशकर, आशा भोंसले और गीतादत्त जैसी चोटी की गायिकाओं के साथ रफी साहब ने एक से बढ़कर एक युगल गीत गाए। लेकिन यह भी सच है कि अपेक्षाकृत कम सफल गायिकाओं को उनके साथ गाने का मौका मिलने से वे सदैव प्रासंगिक रहेंगी। याद करिए, मुबारक बेगम के साथ 'मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही' (हमराही), आरती मुखर्जी संग 'सारा मोरा कजरा छुड़ाया तूने' (दो दिल), कृष्णा कल्ले के साथ 'अजब तेरी कारीगरी रे सरकार' (दस लाख), उषा खन्ना के साथ 'फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम' (ये दिल किसको दूँ) आदि। सुमन कल्याणपुर, सुरैया, शमशाद बेगम जैसी बहुत सी हस्तियों और कविता कृष्णमूर्ति जैसी नई गायिकाओं के साथ भी उन्होंने सदाबहार नगमे गाए हैं।

मोहम्मद रफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे मन में गांठ बांधकर नहीं रखते थे। एक दौर आया जब बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े निर्माता-निर्देशक ने उनसे प्लेबैक कराना बंद कर दिया था लेकिन रफी ने इस बात को दिल पर इतना नहीं लिया कि 'वक्त' में टाइटल सॉन्ग गाने से मना कर दें। लता मंगेशकर जैसी महान गायिका से कभी गीत न गवाने वाले संगीतकार ओ.पी. नैय्यर ने मोहम्मद रफी से भी तीन साल तक किनारा कर लिया था क्योंकि एक बार वे नैय्यर की रिकॉर्डिंग में समय पर नहीं पहुंच पाए थे। बड़ा दिल दिखाते हुए रफी साहब ने खुद पहल की और नैय्यर के पास जाकर खेद प्रकट किया। बात बन गई, गिले शिकवे दूर हो गए। श्रोताओं को नैय्यर और रफी के गाने फिर सुनने को मिले। 'पारसमणी' से संगीतकार के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करनेवाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की सफलता और शोहरत का प्रमुख आधार रफ़ी साहब थे। इस जोड़ी को पहला फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार 'दोस्ती' के लिए मोहम्मद रफ़ी के गानों के कारण मिला। बाद में इस जोड़ी ने भी उनसे गीत गवाने कम कर दिए। उन दिनों राजेश खन्ना स्टारर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजी 'हाथी मेरे साथी' आई, जिसके सभी गाने किशोर कुमार ने गाए। इस फिल्म में जब 'नफरत की दुनिया को छोड़कर' गाने की रिकॉर्डिंग की बारी आई तब हाई पिच के कारण रफी साहब से अनुरोध किया गया जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार लिया। मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत मोहम्मद रफ़ी गायन के क्षेत्र में बेजोड़ हैं। इसीलिए दुनिया को पैंतालीस साल पहले अलविदा कह चुके रफी साहब को चाहने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। हर उम्र के लोग आज भी उनके गीतों के दीवाने हैं।

वक्रोक्ति

भारत शर्मा

लेखक पत्रकार हैं।

होरी: जिन रुढ़ियों के खिलाफ लड़ा, उसी में फंस गया

होरी और यमदूत के बीच हो रही बहस को यमराज ने सुन लिया, तो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उसे अपने चैंबर में बुला लिया। यमराज को उसने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। यमराज साहित्य प्रेमी थे, तो तुरंत पहचान गए, पूछा, तुम प्रेमचंद वाले होरी हो। होरी ने उत्साह में सिर हिलाया, उसे लगा, कि जब यमराज से जान पहचान हो गई है, तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। यमराज ने कहा, पर तुम तो गोदान के नाम पर पैसा देकर आए हो, वो भी एक रुपया। एक रुपए में कौन सी गाय आती है। नियम के हिसाब से गाय दान करना होती है, तब वैतरणी पार होती है। कई पंडित सही बात नहीं बताते और पैसा ऐंठ लेते हैं। होरी ने बताया, महाराज धरती पर बड़ी उथल पुथल चल रही है, गौ रक्षकों का दल जगह-जगह घूम रहा है, उन्होंने किसी के पास गाय देखी, तो जात धर्म पूछे बिना मारने लगते हैं, गाय लेने वाले पर पुलिस मुकदमे अलग से लगा देती है।

मरने के बाद भी होरी की परेशानियां खत्म होने के नाम नहीं ले रही हैं, उसकी आत्मा बैचेन है। उसे अपनी पत्नी धनिया और बेटे गोबर की चिंता है। पूरी जिंदगी वो अपने परिवार को सुख नहीं दे सका और मरने के बाद उन्हें वसीहत के नाम पर साहूकारों का कर्ज ही देकर आया है। होरी को इस बात का भी मलाल है, उसने जिंदगी भर कभी अपने बच्चों के झूठ नहीं बोला, पर आखिरी वक्त में बोलना पड़ा, वह भी गोदान के लिए। झूठ बोलकर गोबर से एक रुपया लेकर गोदान करने का जो काम उसने किया है, उसका बोझ उसकी आत्मा को भारी कर रहा था। होरी की अंतरात्मा ने कहा, तू पूरी जिंदगी जिन रुढ़ियों के खिलाफ लड़ा, अंत समय में उसी में फंस गया, क्योंकि तू भी स्वर्ग नरक में फेर को मानता था पर दुनिया के सामने नास्तिकता को ढ़ोंग रचता था। तुझ पता था, मरने के बाद तुझे वैतरणी पार करने के लिए गाय की जरुरत है और वो तब तक नहीं आएगी, जब तक तू गोदान नहीं करेगा।

अचानक उसकी आत्मा चेतन अवस्था में लौट आई, लगा लंबे समय से सो रही थी। पास यमदूत खड़े थे, जिनके हाथ में कोड़े थे, नरक का दृष्य वैसा ही था, जैसा होरी ने बृम्हाकुमारी आश्रम वालों के पोस्टर में देखा था, कहीं जीव को तेल में तला जा रहा था, तो कहीं उसे कोड़े मारे जा रहे थे। नरक में तैनात यमदूतों की हरकतें वैसी ही थी, जैसी हमारे यहां पुलिस वालों की होती हैं, वैतरणी के लिए वीआईपी घाट बने थे और यमदूत पैसा लेकर लोगों को वैतरणी पार करा रहे थे। होरी गरीब भी था और वो गोदान करके आया था, उसे पूरा भरोसा था, गाय जरुर आएगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब गाय नहीं आई, तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने पास खड़े एक यमदूत से इस बावत पूछताछ की, उसके सुझाव दिया, पैसे दो, तो किसी और की गाय पर बैठाकर वैतरणी पार करा देंगे। होरी ठहरा क्रांतिकारी आदमी, धरती पर भी वह अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा था, उसने यहां रिश्वत देने से इनकार कर दिया। होरी और यमदूत के बीच हो रही बहस को यमराज के सुन लिया, तो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उसे अपने चैंबर में बुला लिया। यमराज को उसने अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। यमराज साहित्य प्रेमी थे, तो तुरंत पहचान गए, पूछा, तुम प्रेमचंद वाले होरी हो। होरी ने उत्साह में सिर हिलाया, उसे लगा, कि जब यमराज से जान पहचान हो गई है, तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकल ही आएगा। यमराज ने कहा, पर तुम तो गोदान के नाम पर पैसा देकर आए हो, वो भी एक रुपया। एक रुपए में कौन सी गाय आती है। नियम के हिसाब से गाय दान करना होती है, तब वैतरणी पार होती है। कई पंडित सही बात नहीं बताते और पैसा ऐंठ लेते हैं। होरी ने बताया, महाराज धरती पर बड़ी उथल पुथल चल रही है, गौ रक्षकों का दल जगह-जगह घूम रहा है, उन्होंने किसी के पास गाय देखी, तो जात धर्म पूछे बिना मारने लगते हैं, गाय लेने वाले पर पुलिस मुकदमे अलग से लगा देती है। होरी ने बताया, वो तो गाय ही देना चाहता था, पर पंडित जी ने लेने से इनकार कर दिया, पैसा देने की सलाह उन्हीं ने दी थी, कहा था गारंटी से वैतरणी पार हो जाएगी।

यमराज ने कहा, ठीक है,पर गाय की कीमत के बराबर पैसा तो देते। होरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपसे क्या छुपा है, आप तो मेरी दशा जानते ही हैं यह एक रुपया भी तो मैंने अपने बेटे से झूठ बोलकर लिया है। होरी ने अपनी बात मजबूती से रखते हुए कहा, प्रभु हम तो कथा वाचकों से सुनते आए हैं, दान श्रृद्धा का होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। यमराज खामोश हो गए, कहने लगे, देख भाई होरी, हमारे हाथ तो कानून से बंधे हैं। तुझे राहत चाहिए, तो भगवान के पास चल, वे ही तेरी मदद कर सकते हैं।

होरी भगवान के पास पहुंचा, उन्होंने सारी कहानी यमराज से सुनी, उसके बाद उन्होंने निर्णय सुनाया, होरी गरीब आदमी है, उसने अपनी औकात से अधिक रुपया गोदान के लिए दिया। उसने अपने परिवार से झूठ बोलकर धर्म की रक्षा की। ऐसे दानी पुरुष यदा कदा ही देखने को मिलते हैं, वरना लोग धरती पर पंडितों को ही चूना लगा देते हैं। हमारा मानना है, कि होरी के मामले को अपवाद स्वरुप लिया जाए, जिससे धरती पर गरीब आदमी की गोदान के लिए प्रेरित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने होरी को वैतरणी पार कराने की अनुमति दे दी।

भगवान का फैसला सुन होरी वापस लौट आया, उसे उम्मीद थी, अब तो उसका कल्याण हो ही जाएगा, पर उसकी किस्मत फूटी थी, उसी वक्त यहां फिर कुछ रक्षक आ गए। उन्होंने कह दिया, हम भगवान के फैसले को नहीं मानते। गौ माता के साथ होने वाले किसी भी अन्याय को बर्दास्त नहीं किया जाएगा। मामला फिर भगवान के दरबार में पहुंचा, तो होरी के पीछे-पीछे वहीं रक्षक भी घुस आए और नारे लगाने लगे। भगवान के पूछने पर उन्होंने कहा, यह हमारी आस्था का सवाल है। आस्था शब्द सुनते ही भगवान भी खामोश हो गए।

तब से परेशान होरी त्रिशंकु बना भटक रहा है, मामला इतना हाईलाईट हो चुका है कि अब यमदूत भी पैसा लेकर वैतरणी पार नहीं करा रहे।

जन बुद्धिजीवी प्रेमचंद

जयंती पर विशेष

चित्रा माली

लेखक महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विवि वर्धा के कोलकाता केंद्र की प्रभारी हैं।

प्रेमचंद को रतननाथ सरशार का उपन्यास 'फसाना ए आज़ाद' बहुत पसंद था। इस पूरे उपन्यास में भारतीय समाज अपनी लोक-संस्कृति और भाषा-अस्मिता के साथ मौजूद था। इसका प्रभाव प्रेमचंद के साहित्य पर भी देखा जा सकता है जिसमें खासतौर पर भारतीय जनजीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भारतीय समाज व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों, शोषण, भेदभाव, ऊंच-नीच, अपमान,ग़रीबी और बेरोजगारी को गांवों और शहरों के चप्पे-चप्पे पर टटोलने का कार्य प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के जेहन में दयानंद सरस्वती का आर्य समाज आंदोलन, विवेकानंद का हिंदू जागरण का सांस्कृतिक आंदोलन और बालगंगाधर तिलक का राष्ट्रीय-मुक्ति आंदोलन 1918 तक सक्रिय रहा। फिर वे इन विचारों से मुक्त हो मार्क्स और लेनिन के विचारों और रूसी क्रांति से प्रभावित होते हैं लेकिन इस काल में भी वे स्वदेशी के विचार से जुड़े रहते हैं। गांधी के प्रति उनका आकर्षक उन्हें गांधी का भक्त या अनुयायी बनने के लिए मजबूर नहीं करता। गांधी के असहयोग आंदोलन के आह्वान पर प्रेमचंद सरकारी नौकरी से इस्तीफा जरूर दे देते हैं।

प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकताओं को महसूस किया और राष्ट्र के बहुधर्मी,बहुभाषी,बहुलतावादी स्वरूप और संस्कृति के यथार्थ बिंब को कैसे गूंथा जाए- यह प्रेमचंद के लिए बुनियादी समस्या थी। टॉलस्टॉय उन्हें पसंद थे लेकिन उनका बहुत अधिक प्रभाव प्रेमचंद पर नहीं पड़ा। दरसअल,पश्चिम का कोई उपन्यास उनका 'मॉडल' नहीं था। वे तो भारतीय गांव और शहरों को उसकी आंतरिक संस्कृति के साथ समग्रता में अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठकों को परोस देना चाहते थे। प्रेमचंद ने अपने युवा काल में असरारे मुआबिद, हमखुर्मा व हम सबाब,बज़ारे हुस्न,जलवाए ईसार, नौशाए काफ़ियत और चौगाने हस्ती की रचना की। प्रेमचंद उर्दू साहित्य की परंपरा से आकर हिंदी के सर्वाधिक सफल,लोकप्रिय और चर्चित साहित्यकार बन गए। 1924 से 1936 तक वे हिंदी-हिंदुस्तानी की गांधीवादी रंगत में आ गए। उनकी रचनाएं सांस्कृतिक-राजनीतिक क्रांति के घेरे में भारत की राजनीति को 'अंतर्वस्तु' बना कर जनता की वेदना-यातना का प्रतिनिधित्व करने लगी। उनकी रचनाओं के केंद्र में असंगठित मजदूर-किसान,अनपढ़ जन, व्यवस्थागत और गरीबी से शोषित स्त्री-पुरुष स्थापित होते चले गए। भारत का स्वंतत्रता आंदोलन, देशभक्ति, राजभक्ति, राष्ट्रीयता और अनेक तरह की वैचारिक संघर्ष के साथ आगे बढ़ा है। संघर्ष के इन ऐतिहासिक क्षणों में प्रेमचंद एक साक्षी बनकर लगातार मौजूद रहे और उनका सर्जक उन क्षणों का सामाजिक-संस्कृतिक इतिहास अपनी रचनाओं में रचता रहा। प्रेमचंद की साहित्य सृजन की प्रक्रिया संघर्ष और क्रांति,बदलाव और विद्रोह से निर्मित हुई है। यही कारण है कि उनका रचना- संसार साम्राज्यवाद विरोधी,व्यक्तिवाद विरोधी,उपनिवेशवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी और संप्रदायवाद विरोधी है। साम्प्रदायिकता,हिंदू-मुस्लिम एकता,साझी संस्कृति और विरासत की जब भी बात की जाती है तो हमारे जेहन में प्रेमचंद के लेख व रचनाएं घूमने लगती है। इन लेखों और रचनाओं के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अगर किसी के विचारों और शब्दों को पढ़कर ऐसा लगे कि वे आज के समय के यथार्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं तो आश्चर्यचकित होने के साथ कई और प्रश्नों को भी उठाता है कि इतने वर्षों के बाद भी प्रेमचंद के लेखों व रचनाओं के बाद उनकी टक्कर की कोई और रचना या कृति क्यों नहीं है? जिनका उदाहरण लिया जा सके। प्रेमचंद समाज में फैल रही असहिष्णुता, सांप्रदायिकता, हिंसा, घृणा और अव्यवस्था के खिलाफ

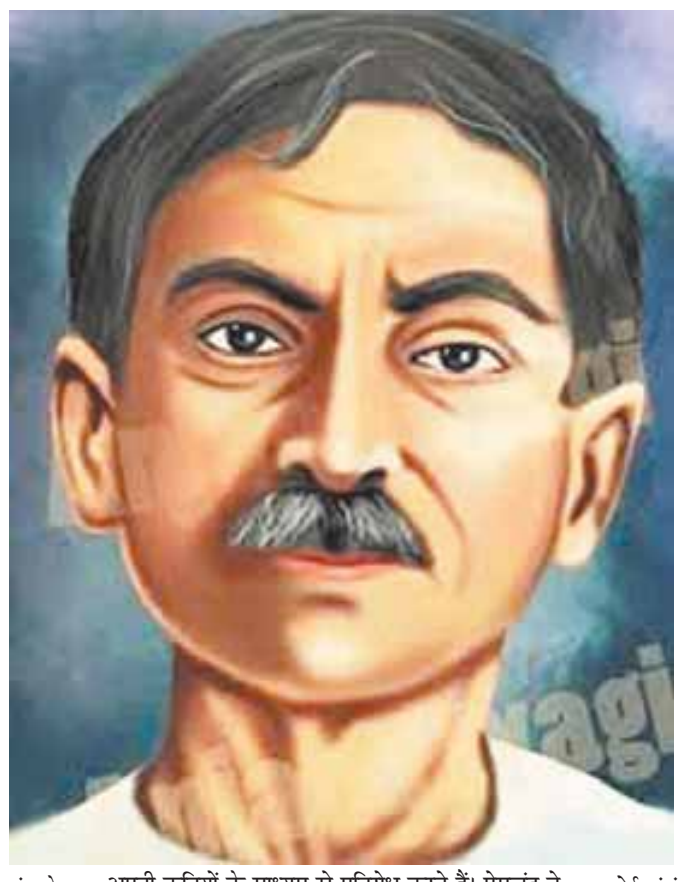

अपनी कृतियों के माध्यम से प्रतिरोध करते हैं। प्रेमचंद ने 1930 में 'हंस' पत्रिका के संपादन का कार्य किया। इसके पूर्व भी वे कई पत्र पत्रिकाओं के संपादन का कार्य कर रहे थे लेकिन 'हंस' पत्रिका के माध्यम से वे लेखक व लेखन की स्वतंत्रता और समाज के यथार्थ को दृढ़ता से प्रस्तुत कर रहे थे। हिंदू-मुस्लिम एकता की थीम पर आधारित एक महत्वपूर्ण निबंध उन्होंने लिखा जो सबसे पहले 1931 में 'हंस' में ही प्रकाशित हुआ था। हिंदुस्तान के परिपेक्ष्य में 1930 का दशक साम्प्रदायिकता के उभार का दौर था जिसकी चरम परिणति 1947 के विभाजन का सबब बनी। 1930 में प्रेमचंद जिस साम्प्रदायिक वातावरण पर चिंता जाहिर कर रहे थे कमोबेश वही वातावरण आज भी जस का तस बना हुआ है यह घोर चिंता का विषय है क्योंकि आज जब हम आधुनिक,प्रगतिशील और सेकुलर होने का दंभ भरते हैं तो वह केवल हमारे बाहरी हिस्से में परिलक्षित होता है जबकि आंतरिक रूप से आज भी हम धर्म,जाति और लिंग के भेदभाव परक पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं।

प्रेमचंद लिखते हैं कि 'साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है,उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है। इसलिए वह उस गधे की भांति है, जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों पर रोब जमाती है। धर्म और संस्कृति के संबंध में प्रेमचंद के विचार क्रांतिकारी लगते है, वह हंस में लिखे अपने लेख में लिखते हैं' हिंदू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, मुसलमान अपनी संस्कृति को,दोनों ही अभी तक अपनी-अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं,यह भूल गए हैं कि अब न कहीं हिंदू संस्कृति है और न मुस्लिम संस्कृति और न कोई अन्य संस्कृति,अब संसार में केवल एक संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति,मगर आज भी हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोए चले जाते हैं,हालांकि संस्कृति का धर्म से कोई संबंध नहीं..... फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वह कौन सी संस्कृति है,जिसकी रक्षा के लिए साम्प्रदायिकता इतना जोर बांध रही है,वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है,निरा पाखंड, यह सीधे आदमियों को साम्प्रदायिकता की और घसीट लाने का केवल एक मंत्र है और कुछ नहीं'। हिंदू-मुसलमानों की साझी संस्कृति और विरासत को प्रेमचंद की रचनाओं में देखा जा सकता है जहां मुस्लिम पात्र हिंदुओं के त्योहारों,होली और दिवाली उत्साह से मनाते दिखाई देते हैं। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की दुनिया,उनके सपनों और उनके दुखों को भी दर्शाया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में दोनों ही समुदायों के आंतरिक जीवन को एक समान रूप में चित्रित किया है। प्रेमचंद कहते हैं कि 'साहित्यकार का लक्ष्य देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं है,बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है'। प्रेमचंद के हर उपन्यास की अपनी एक अलग पृष्ठभूमि है इसलिए उनके उपन्यासों को सामाजिक,आर्थिक,राजनीतिक या किसान जीवन के उपन्यास जैसे किसी विशेषण में नहीं बांधा जा सकता हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों में नारी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है। प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र जो आत्मकथा और कहानी का मिश्रित प्रयोग है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था के अमानवीकरण पर व्यंग्य किया गया है। सृजनात्मकता की इस विकास यात्रा में कई पड़ाव आते हैं और वे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीच गांधी विचार के यूटोपिया से भी उनका मोह भंग होता है और वे आदर्शवाद से परे आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं। उनकी खोज भारतीय ढंग के समाजवाद की है। प्रेमचंद ने अंततः सभी विचारधाराओं के मॉडल को नकारते हुए कहा कि जनता को जानना होगा,वरना व्यवस्था उनके जीवन को हड़प जाएगी। साहित्य की सामान्य समझ रखने वाले व्यक्ति भी प्रेमचंद से उनकी कृतियों से किसी न किसी रूप में परिचित हैं । प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों,कहानियों और निबंधों के माध्यम से तत्कालीन समाज व्यवस्था, साम्प्रदायिकता और औपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के कई पक्षों को सामान्यजन की भाषा में सहजता से प्रस्तुत किया है। वर्तमान समय के साहित्य में सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक,आर्थिक और नैतिक प्रश्नों में प्रेमचंद की उपस्थिति का कारण उनके संपूर्ण चिंतन और साहित्य सृजन में मानव मुक्ति की तलाश है। प्रेमचंद की लेखन परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ईमान की बात की जाए और जो चंद लेखक लेखन की इस परंपरा को कायम किए हुए हैं उनके साथ खड़े हों उनका मनोबल बढ़ाए,जिससे अंतिम व्यक्ति के दर्द को उसकी संवेदना को समझा जा सके।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने चिचोली में किराना दुकानों का किया औचक निरीक्षण

बैतूल। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों की सघन जांच एवं नमूने लिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन शैलेंद्र बड़ोनिया के मार्गदर्शन में 30 जुलाई को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मीना कुमारे द्वारा तहसील चिचोली की किराना दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सोनी इंटरप्राइजेज, संदीप ट्रेडर्स किरणा से 14 सैंपल जीरा लूज, काली मिर्च, अजवाइन, राई, मेथी लूज, हींग, नोवा घी, पतंजलि घी, गोवर्धन घी, गुलाब जामुन, मिक्स नमक आदि के नमूने लिए गए। लिए गए सैंपल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। यह करवाई सतत जारी रहेगी।

मोहित गर्ग बने मीडिया प्रभारी

बैतूल। जिला वैश्य महासम्मेलन मध्यप्रदेश की बैतूल जिला इकाई की कार्यकारिणी पुर्नगठित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष, अखिलेश गोठी, जिला उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल, जिला महामंत्री हेमंत पगारिया, अनिल बांगड, संजय अग्रवाल, निर्मल सुराणा, पन्नालाल जायसवाल, जिला मंत्री जगदीश अग्रवाल, उमेश पेठे, रेखा शिवहरे, जिला कोषाध्यक्ष जयदीप सिंह रूनवाल, मीडिया प्रमुख मोहित गर्ग, जिलाध्यक्ष युवा ईकाई अनंत अग्रवाल, आरपी सोनी, अरविंद कुमार मालवीय कार्यालय मंत्री, बैतूल, जिला कार्यकारिणी सदस्य संजय खंडेलवाल भौरा, जयश संघवी, महेंद्र (पिल्लु) जैन, अभिषेक खंडेलवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल, मुलताई। तहसील अध्यक्ष शाहपुर विक्की नायक, घोडाडोंगरी डॉ. कृष्ण गोपाल अग्रवाल, चिचोली जितेन्द्र सुर्यवंशी, मुलताई देवेन्द्र (जैन) धोपाडे, आमला संजय साहू, भैंसदेही विनोद सोनी, आठनेर रजनीश जायसवाल और महिला कार्यकारिणी बैतूल जिला महिला इकाई अध्यक्ष अमिता गुप्ता, संरक्षक राजकुमारी जैन, जिला प्रभारी प्रेमलता खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष विनीत गर्ग, जिला महामंत्री नूतन लुहाडिया, जिला मंत्री माधुरी खंडेलवाल जिला कोषाध्यक्ष अंजना खंडेलवाल, सह कोषाध्यक्ष श्रदा खंडेलवाल, कार्यकारिणी सदस्य ममता खंडेलवाल, सरिता खंडेलवाल, कंचन जैन, पुष्पा खंडेलवाल, निशा खंडेलवाल, सुनीता खंडेलवाल, भावना जैन को बनाया गया है।

जेवलिन प्रतियोगिता का आयोजन 7 अगस्त को

देवास। जिला एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जेवलिन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य नीरज चोपड़ा द्वारा जो ओलंपिक में मेडल जीता था तब भारतीय एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा फैसला किया था कि 7 अगस्त को जेवलिन डे पूरे भारत वर्ष में मनाया जाए। नीरज चौपड़ा की इस उपलब्धि पर यह दिवस मनाने का फैसला किया है। उनके दिशा अनुसार देवास जिला एथलेटिक एसोसिएशन जेवलिन प्रतियोगिता का आयोजन 7 अगस्त को प्रातः 10 बजे कुशाभाव ठाकरे स्टेडियम विकास नगर में आयोजित की जाएगी। इसमें सिर्फ स्कूल के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। उक्त जानकारी देवास जिला एथलेटिक एसोसिएशन सचिव अनिल श्रीवास्तव ने दी।

मानव तस्करी के विरुद्ध चला जागरूकता अभियान

बैतूल। ग्राम जाड़ीढाना, ग्राम पंचायत जोगली, ब्लॉक चिचोली में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक पल्लवी टाकरकर के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों, विशेषकर मजदूर वर्ग को मानव तस्करी के प्रकार, इसके खतरों और इससे बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मजदूरों को बताया कि अगर वे रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं, तो उन्हें उस व्यक्ति या ठेकेदार की पूरी जानकारी रखनी चाहिए जो उन्हें काम पर भेज रहा है। यह जानकारी उनके सुरक्षित और योजनाबद्ध पलायन के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में ग्रामीणों को 1800 120 1121 नंबर की मजदूर हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी गई, जिससे जरूरत के समय पर वे सहायता प्राप्त कर सकें।

औसत आंकड़े के लगभग आधे के पास पहुंची बारिश, फिर भी जलाशय खाली

कहीं 20 प्रतिशत, तो कहीं 40 प्रतिशत ही भरे डैम

संजय द्विवेदी, बैतूल। बारिश सीजन का करीब डेढ़ माह पूरा हो चुका है, लेकिन जलाशयों का पेट अब भी खाली है। जबकि जिले में पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष 23.1 मिमी अधिक बारिश हो चुकी है और एक-दो दिन में बारिश का यह आंकड़ा औसत बारिश के आधे तक पहुंच जायेगा। लेकिन बैतूल डिवीजन के अधिकांश जलाशय अभी भी खाली पड़े है। कहीं जलाशयो में 20 प्रतिशत जल संग्रहण हुआ है, तो कहीं 40 फीसदी ही पानी आया है। यह पानी भी पिछले एक सप्ताह के भीतर हुई बारिश के बाद जलाशयों में पहुंचा है। इसके पीछे जानकार यह कारण बता रहे है कि इस वर्ष जिले में बारिश की रफ्तार धीमी रही। इसी के बीच जुलाई में सावन माह की शुरूआत के बाद लगभग 15 दिन बारिश पर ब्रेक लगा रहा। जिससे जलाशयों में जो पानी पहुंचा था, वह भी कम हो गया। माचना एनीकेट तो पूरी तरह सूख गया था और नगरपालिका को ताप्ती से पानी लाकर शहर में सप्लाई करना पड़ा। इधर तेज बारिश नहीं होने से बैतूल डिवीजन के 104 जलाश्यों में भी पानी नहीं पहुंचा और यदि बैतूल के जलाशयों की प्यास सितंबर माह तक नहीं बुझी, तो रबी की फसलों पर संकट के बादल मंडरा सकते है।

अभी तक जिले में 522.5 मिमी बारिश दर्ज : जिले में मानसून को आए लगभग डेढ़ माह हो चुका है। इस दौरान जिले में करीब 522.5 बारिश हुई। जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 12.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि 30 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे यानि पिछले 24 घंटे में तहसील बैतूल में 12.0, घोड़ाडोंगरी में 19.0, चिचोली में 21.0, शाहपुर में 15.0, मुलताई में 9.0, प्रभात पट्टन में 14.4, आमला में 6.0, भैंसदेही में 12.0, आठनेर में 8.1. तथा भीमपुर में 7.0 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। जबकि पिछले साल 499.4 मिमी बारिश दर्ज की गई थी। बता दे कि जिले की औसत वर्षा 1083.9 मिमी है।

जिले के दो डिवीजनों में है 192 छोटे-बड़े जलाशय : जिले में दो डिवीजन है, जिसमें कुल 192 छोटे-बड़े जलाशय शामिल है। पहला डिवीजन बैतूल है। बैतूल डिवीजन में 102 लघु सिंचाई परियोजना है तथा 1 मध्यम सिंचाई परियोजना सांपना जलाशय है। इसके अलावा निर्माणाधीन घोघरी, मेंढा, गढ़ा और शीतलझिरी परियोजनाओं का काम चल रहा है। वहीं मुलताई डिवीजन में कुल 88 जलाशय है। जिसमें 6 मध्यम सिंचाई परियोजना चंदोरा, पारसडोह, बुंडाला, वर्धा, देहगुड, सोनखेड़ी है। इसमें से चंदोरा 9 प्रतिशत, पारसडोह 46 प्रतिशत, बुंडाला 20 प्रतिशत, वर्धा 20 प्रतिशत, देहगुड 4 प्रतिशत और सोनखेड़ी 20 प्रतिशत भरे है। इसके अलावा मुलताई डिवीजन में 82 लघु सिंचाई परियोजना है। हालांकि जिले के डैमों में सबसे अच्छी स्थिति सतपुड़ा जलाशय की है, यहां डैम का वॉटर लेवल क्षमता के अनुरूप मेंटेंन किया जा रहा है। पानी का लेवल बढने पर गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन अन्य जलाशयों में अभी भी क्षमता से 20 से 40 प्रतिशत ही पानी आ पाया है।

नहीं भरे जलाशयों के पेट, तो कैसे होगी सिंचित : हालांकि अभी बारिश के सीजन को ढ़ाई माह का समय बचा हुआ है। इन ढाई माह में जिले में तेज बारिश नहीं हुई और जलाशयों का पेट नहीं भरा तो हजारों हेक्टेयर में लगने वाली आगामी रबी फसल की सिंचित के लिए मुश्किले खड़ी हो जायेगी, क्योंकि जिले के मध्यम और लघु डैमों के सहारे ही जिले के अधिकांश क्षेत्रों में रबी फसल की सिंचाई होती है। यदि डैम ही लबालब नहीं रहेगे तो पानी का संकट खड़ा हो जायेगा। हालांकि सभी उम्मीदें अभी बारिश से ही है। बीते दो दिनों से बैतूल जिले में बारिश भी हो रही है। लेकिन बरसने के मामले में बादलों की मेहरबानी कम ही है।

माचना में आया भरपूर पानी, शहर में सप्लाई: विगत दिनों हुई बारिश के बाद माचना में भी पर्याप्त पानी आ गया है। जिसके बाद शहर में पेयजल सप्लाई को पुनः एक दिन के अंतराल में शुरू किये जाने पर विचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक-दो दिन में शहर के वार्डो में एक दिन के अंतराल में पानी सप्लाई की व्यवस्था कर दी जायेगी। जबकि कुछ दिनों पहले माचना सूखने के बाद शहर में दो दिन के अंतराल में पेयजल सप्लाई हो रही थी और लोगों को पानी के लिए परेशान भी होना पड़ रहा था, लेकिन पिछले दिनों से हो रही बारिश के बाद माचना की स्थिति में काफी सुधार आया है। अभी माचना के 4 गाले खोलकर पानी के साथ आने वाले कचरे सहित अन्य सामग्रियों को बहाया जा रहा है और 4 गाले को 4-4 फीट पर मेंटेंन कर रहे है।

इनका कहना है -

जिले में 192 छोटे-बड़े डैमों में 20 से 40 प्रतिशत पानी आया है। अभी बारिश का काफी समय शेष है। उम्मीद है कि इन दिनों में तेज बारिश होगी और जल्द ही जिले के सभी डैम लबालब भर जायेगे।

- आरके सिंह, ईई, जल संसाधन विभाग, बैतूल

ठेका कंपनी ने भी 2 किमी मेंटनेंस कर सड़क अधूरी छोड़ी

भीवकुंड प्रधानमंत्री सडक़ हुई गड्ढों में तब्दील

बैतूल। जिले के भैंसदेही नगर के अटल बिहारी स्टेडियम के बाजू से भिवकुंड जाने वाली प्रधानमंत्री सडक़ पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गई है। इस सडक़ पर वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सडक़ निर्माण या सडक़ की मरम्मत के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिससे लोगों में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बनी हुई है। बताया जाता है कि 4.61 किमी का यह मार्ग पूरा खराब हो गया है। जिसके मेंटनेंस का ठेका मेसर्स भगवती इंटरप्राईजेस मुरैना को दिया था, लेकिन ठेका कंपनी ने भीवकुंड ग्राम से भैंसदेही की ओर मात्र 2 किमी मार्ग पर डामरीकरण कर मेंटनेंस का कार्य किया, बाकी रोड वैसे ही छोड़ दी। जबकि इस सडक पर सबसे ज्यादा खराब स्थिति स्टेडियम से जामठी शिवम पब्लिक स्कूल के टेकड़े तक है। जगह-जगह गड्ढे हो चुके है। इन गड्ढों में बारिश का पानी थम हुआ है। जिसके कारण वाहन चालकों को गड्ढे समझ नहीं आते और वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे है। बता दे कि इसी मार्ग पर शिवम स्कूल के बच्चे भी आवागमन करते है। इन्हें भी रोजाना खराब मार्ग की परेशानियों से जुझना पड़ता है। लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से सडक़ पर बने गड्ढे और भी बड़ा आकार लेते जा रहे है। जिससे कुछ ही दिनों में यह सडक़ पूरी तरह खराब होकर बिखर जायेगी। लोगों ने सडक की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिल सके।

वाहनों को भी पहुंच रहा नुकसान : सडक़ पर गड्ढों की वजह से वाहन चालक तो चोटिल हो ही रहे है, साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वाहन चालकों का कहना है कि बार-बार वाहनों के गड्ढे में जाने से वाहनों के एक्सल टूट रहे है। वाहनों में टूट-फूट हो रही है। जिसके कारण वाहन चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। खराब सडक के कारण सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालक परेशान है। वाहन चालकों का समझ ही नहीं आता है कि वाहन कहां से निकाले। ऐसे में वाहन चालक गड्ढों से बचने के चक्कर में गिरकर चोटिल भी हो रहे है।

नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

बच्चों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

देवास। उड़ान स्पोर्ट्स विकास समिति, सोनकच्छ द्वारा खेल एवं युवा कल्याण विभाग, देवास के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जन जागृति अभियान के अंतर्गत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन नगर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य बच्चों एवं नवोदित खिलाड़ियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराना तथा उन्हें स्वस्थ, अनुशासित एवं खेलपरक जीवन की ओर प्रेरित करना था। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी सोभाग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नशा केवल शरीर ही नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व को क्षीण करता है। युवाओं को चाहिए कि वे खेलों को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, जिससे न केवल वे आत्मविकास करें, बल्कि समाज को भी एक सकारात्मक दिशा दें। युवा समन्वयक जावेद पठान ने अपने उद्बोधन में कहा, नशा उन्मूलन कोई एक व्यक्ति की नहीं, संपूर्ण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम सब मिलकर संकल्प लें, तभी इसका समूल नाश संभव है। कार्यक्रम में फुटबॉल कोच विल्सन निनामा एवं वॉलीबॉल कोच आयुष गांगुड़े की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। दोनों प्रशिक्षकों ने खेलों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बच्चों को नशे से दूर रहने और खेलों में निरंतर संलग्न रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सचिन सिंह परिहार ने उपस्थित बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। बच्चों ने पूरे उत्साह एवं दृढ़ निश्चय के साथ यह संकल्प लिया कि वे स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहेंगे और अपने आस-पास के लोगों को भी इसके कुप्रभावों से सजग करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले बच्चों को सोभाग सिंह ठाकुर द्वारा पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। नशे से दूरी है जरूरी इस भाव को आत्मसात करते हुए यह कार्यक्रम समाज में एक जागरूक चेतना का संचार करता प्रतीत हुआ। खेलों के माध्यम से यदि हम युवाओं को जीवन की सही दिशा दिखा सकें, तो वह दिन दूर नहीं जब एक स्वस्थ, समर्थ एवं नशा-मुक्त भारत का सपना साकार होगा।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को गर्भ संस्कार विषय पर दिया प्रशिक्षण

आयुष कार्यालय में हुई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक

बैतूल। जिले की समस्त महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक का आयोजन जिला आयुष कार्यालय बैतूल में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने की, जबकि नोडल अधिकारी डॉ. मनक धुर्वे एवं सहायक नोडल अधिकारी डॉ. अजय मांडवे विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं को गर्भ संस्कार, प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भिणी परिचर्या, प्रसव पश्चात देखभाल, टीकाकरण, कुपोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन जानकारी दी गई। गर्भ संस्कार विषय पर डॉ. विनीता महादुले, डॉ. लक्ष्मी किशनानी और डॉ. शारदा चौधरी ने विस्तृत व्याख्यान देते हुए बताया कि गर्भ संस्कार क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है और यह क्यों जरूरी है। उन्होंने यह भी समझाया कि महिला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यकर्ता समाज की महिलाओं के निकट रहती हैं, इसलिए वे गर्भ संस्कार के लाभों को समझाकर महिलाओं को प्रेरित कर सकती हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी संस्कारी बन सके।

जेईई, नीट एवं सीएएलटी कोचिंग की प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त को

बैतूल। आकांक्षा योजना के अंतर्गत जेईई, नीट एवं सीएएलटी की कोचिंग के लिए कक्षा 10वी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 676 विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन किए है। जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त ने बताया कि इन विद्यार्थियों की प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त को समस्त विकासखंडों के उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर में दोपहर 12.30 बजे से 2.30 तक आयोजित होगी। उन्होंने समस्त आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि पर समय से 1 घंटा पूर्व प्रातः 11.30 बजे दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन की प्रतिलिपि, कक्षा 10वी की अंकसूची, आय प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ संबंधित विकासखण्ड के परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा देवास के स्थापना दिवस को रजत जयंती सम्मान समारोह के रूप में मनाया

देवास। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन शाखा देवास ने शाखा स्थापना दिवस को स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती सम्मान समारोह के रूप में होटल रामाश्रय में कार्यक्रम आयोजित कर मनाया। जिसमें बड़ी संख्या मे देवास की प्रबुद्ध महिलाओं ने अपनी उपस्थिति प्रदान की जिनमें शहर की अन्य महिला संस्था एवं समाज की महिलाएं शामिल रही। देवास की मां चामुंडा शाखा ने भी उपस्थित हो कर कार्यक्रम में भाग लिया। शाखा अध्यक्ष शकुंतला सोनी ने बताया कि हमारी शाखा समाज सेवा एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 25 वर्षों से लगातार सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस उपलब्धि पर शाखा द्वारा अपनी समस्त पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सदस्यों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ऑपरेशन सिंदूर एवं लव जिहाद पर लघु नाटिकाएं प्रस्तुत की गई। बहनों द्वारा देश के अनेक प्रांतो की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर प्रदर्शन किया गया साथ ही नृत्य प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देवास नगर निगम की महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल को स्वच्छता मिशन में देश के 3 लाख जनसंख्या तक के शहरों में प्रथम आने पर सम्मान पत्र प्रदान किया गया। श्रीमती अग्रवाल द्वारा अपने उद्बोधन में इस उपलब्धि के लिए नगर की जनता एवं सदन में उपस्थित बहनों की भागीदारी की सराहना की। कार्यक्रम में विशेष अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष राजकुमारी बागड़ी, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष इंदु सोमानी, राष्ट्रीय अंचल प्रमुख सुमन मूंदड़ा ने अपने उद्बोधन में शाखा एवं संस्था की 25 वर्ष की यात्रा एवं उपलब्धियां को स्मरण किया एवं इस उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा की। कार्यक्रम में शाखा की महिला सशक्तिकरण प्रमुख डॉक्टर किरण भार्गव को उनके सतत किए गए कार्यों के लिए महिला गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सुमन मूंदड़ा को शाखा सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पदों तक अपनी पहचान बनाने के लिए शाखा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राजश्री सोनी एवं शीतल सोनी द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम समापन पर शाखा सचिव श्रीमती विजयलक्ष्मी भूतड़ा द्वारा आभार प्रदर्शन किया।

टीबी मरीजों के लिए टीएसीसी लिमिटेड की स्वास्थ्य सेवा पहल- छह माह तक वितरित होंगी

नि-क्षय पोषण आहार किट

देवास। भारत सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, टीएसीसी लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के तहत एक महत्वपूर्ण जनस्वास्थ्य पहल नि-क्षय पोषण योजना का शुभारंभ मुख्य अतिथि ऋतुराज सिंह, जिला कलेक्टर, देवास की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर देवास जिला अस्पताल परिसर से 250 उपचारित टीबी मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार किट वितरित कर इस पहल की औपचारिक शुरुआत की गई। इस पहल के अंतर्गत, टीबी से पीड़ित 1000 मरीजों को आगामी छह माह तक प्रतिमाह निःशुल्क नि-क्षय पोषण आहार किट प्रदान की जाएगी। यह वितरण ब्लॉक स्तर पर देवास जिला क्षय नियंत्रण केंद्र (डीटीसी), बरोठा, टोंकखुर्द, सोनकच्छ, बागली, कन्नौद एवं खातेगांव में प्रत्येक माह आयोजित होगा। वितरण प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति में किया जाएगा तथा लाभार्थियों से सहमति पत्र लेकर आवश्यक दस्तावेजों का संधारण किया जाएगा। कार्यक्रम में टीएसीसी लिमिटेड के वरिष्ठ पदाधिकारी रमेश खेतान, अतुल यादव, विकास शर्मा, राजेश मलिक, उमाकांत गुप्ता, शिव विजयवर्गीय, मोहित दशोरा, अनुभव जॉन, मोहित त्रिपाठी एवं डॉ सतीश सैनी उपस्थित थे। कार्यक्रम में डॉ. सरोजिनी बेक (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी), डॉ. अमरीन शेख (जिला टीबी अधिकारी), निशा डाल्के (प्रिंसिपल जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र), हुकुम परमार (स्टोर प्रभारी), मोहन शिंदे (एसटीएस), राजेश जोशी (टीबीएचवी) एवं अन्य चिकित्सकों की उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचएमओ) डॉ. सरोजिनी बेक ने टीएसीसी लिमिटेड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, टीबी मरीजों को समय-समय पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति की नियमित जांच कराते रहना चाहिए। उन्हें अपने वजन, हीमोग्लोबिन और बलगम की जांच के साथ नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना चाहिए। समय पर जांच और दवा सेवन से टीबी पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की पोषण आहार किट से मरीजों को शारीरिक रूप से मजबूत बने रहने में मदद मिलेगी, जिससे इलाज का असर और तेज होगा। इस अवसर पर टीएसीसी लिमिटेड के वरिष्ठ पदाधिकारी रमेश खेतान ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि, हमारी कंपनी जनकल्याण के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती है और ऐसे सामाजिक उत्तरदायित्वों में सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहती है। हाल ही में टीएसीसी लिमिटेड द्वारा महिला स्वास्थ्य शिविर का भी सफल आयोजन किया गया, जिसका लाभ स्थानीय समुदाय की अनेक महिलाओं को मिला।टीएसीसी की इस पहल का उद्देश्य न केवल उपचार के समय को कम करना और इलाज के परिणामों को बेहतर बनाना है, बल्कि विशेष रूप से ग्रामीण एवं कमजोर वर्गों में टीबी के प्रति जागरूकता और पोषण सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित करना भी है। इस अवसर पर कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने टीएसीसी लिमिटेड का आभार व्यक्त किया और इस अभियान में सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि, ऐसे प्रयासों से न केवल मरीजों को सहायता मिलती है, बल्कि जिला प्रशासन को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों को पूरा करने में बल मिलता है। उन्होने अपने विचार साझा करते हुए ने कहा, भारत का व्यापक टीबी उन्मूलन दृष्टिकोण सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है, जिससे टीबी के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट आई है और स्वास्थ्य प्रतिक्रिया ढाँचा मजबूत हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी, नवोन्मेषी देखभाल समाधानों और सामुदायिक सहभागिता पर निरंतर जोर देने के साथ, भारत 2025 में टीबी मुक्त राष्ट्र के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अच्छी स्थिति में है। उन्होंने यह भी कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी इस लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम के समापन पर, श्री खेतान ने सिविल अस्पताल देवास की पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, टीएसीसी लिमिटेड का उद्देश्य केवल उद्योग संचालन नहीं, बल्कि समुदाय के समग्र विकास में सहभागी बनना है। हम भविष्य में भी समय-समय पर इसी प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं एवं सामाजिक विकास पहलों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ मिल सके।

संक्षिप्त समाचार

नशे से दूरी है जरूरी अभियान का क्रियान्वयन, कलेक्टर सहित अन्य ने शपथ ली

विदिशा (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा संचालित जागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी के संदर्भ में नागरिको के साथ-साथ अधिकारी, कर्मचारियों के मध्य जनजागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को लंबित आवेदनो की समीक्षा बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत चैबे ने उक्त अभियान की निहित बिन्दुओं को सांझा किया है। ततपश्चात कलेक्टर सहित अन्य सभी अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा शपथ ली गई है। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने शपथ का वाचन किया, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर सहित संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर व विभिन्न विभागो के अधिकारियों ने शपथ को दोहराया है। कार्यक्रम में हमारा यहीं संदेश, नशामुक्त हो मध्यप्रदेश, पुलिस द्वारा प्रकाशित पेम्पलेट और संदेश प्रवर परिवार के द्वारा नशा मुक्त अभियान के रेखांकन पर आधारित फोल्डर का वितरण किया गया है।

कृषि स्थायी समिति की बैठक 31 को

विदिशा (निप्र)। जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति के सभापति की अध्यक्षता में समिति की बैठक 31 जुलाई को आयोजित की गई है। यह बैठक जिला पंचायत के सभागार में दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। समिति के सदस्य सचिव व किसान कल्याण कृषि विभाग के उपसंचालक ने बैठक एजेंडा बिंदुओं के संदर्भ में बताया कि कृषि विभागः-योजनाओं के पंजीयन की प्रकिया।संचालित योजनाओं के नाम एवं अनुदान राशि।मृग उपार्जन की जानकारी। खाद बीज की उपलब्धता। विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का अनुमोदन। तथा कृषि अभियांत्रिकी संचालित योजनाओं के नाम एवं अनुदान राशि। कस्टम हायरिंग सेंटर लक्ष्य एवं पूर्ति। सम्पूर्ण योजनाओं की जानकारी एवं लक्ष्य पूर्ति (वर्ष 2024-25)।विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का अनुमोदन। पशुपालन विभाग की योजनाओं के पंजीयन की प्रक्रिया।संचालित योजनाओं के नाम एवं अनुदान राशि। सम्पूर्ण योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति (वर्ष 2024-2025) 1श पशुपालन विभाग के सम्पूर्ण उपस्वास्थ्य केन्द्रो की जानकारी। विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का अनुमोदनमत्स्य विभाग की योजनाओं के पंजीयन की प्रक्रिया। संचालित योजनाओं के नाम एवं अनुदान राशि। सम्पूर्ण योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति (वर्ष 2024-2025)उद्यानिकी विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का अनुमोदन।योजनाओं के पंजीयन की प्रकिया। संचालित योजनाओं के नाम एवं अनुदान राशि एवं पीएमएफएमई, पीडीएमसी, एमआईडीएच योजनाओं की विस्तृत जानकारी। सभी योजनाओं की जानकारी लक्ष्य पूर्ति (वर्ष 2024-2025)।विभिन्न योजनांतर्गत प्राप्त लक्ष्यों का अनुमोदन।

प्रतिबंध के बावजूद अमरगढ़ वाटरफॉल आने वाले सैलानियों के 05 वाहनों पर की गई चालानी कार्रवाई

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार सीहोर जिले के वाटरफॉल, बांध, नदियों के तटीय क्षेत्र सहित अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर सैलानियों को जाने से रोकने के लिए इन स्थानों के मार्गो पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। शाहगंज थाना पुलिस द्वारा प्रतिबंध के बावजूद अमरगढ़ वाटरफॉल आए 05 टूरिस्ट वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री बालागुरू के. द्वारा वर्षा ऋतु में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिले के दिगंबर वाटरफॉल, अमरगढ़ वाटरफॉल, कालियादेव वाटरफॉल, बुधनी मिडघाट क्षेत्र, कोलार बांध क्षेत्र, झोलियापुर बैराज, नर्मदा तटीय सहित सभी जोखिमपूर्ण स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ताकि इन स्थानों पर होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्रतिबंध का उल्लंघन कर इन स्थानों पर जाने वाले लोगों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने सभी नागरिकों से बांध, तालाब, झरनों सहित अन्य जोखिमपूर्ण स्थानों पर नहीं जाने की अपील करते हुए कहा है कि इस प्रतिबंध का पालन करें और वर्षा ऋतु के दौरान अपने जीवन की सुरक्षा को महत्व देते हुए इन स्थानों पर ना जाएं।

बेतवा नदी में बही महिला का शव बरामद

विदिशा (निप्र)। गंजबासौदा के गंज वाले पुल के पास बेतवा नदी में शुक्रवार को शंकर जी की पार्थिव प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्राम मुर्टरा निवासी श्रीमती राजकुमारी दांगी पत्नी स्व. जसवंत सिंह दांगी फिसलकर गिरने से नदी में बह गई थी। खोजबीन हेतु आज तीसरे दिन सुबह से सर्चिंग अभियान डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड मयंक कुमार जैन के नेतृत्व में शुरू किया गया। भोपाल से आई एनडीआरएफ की टीम द्वारा 4 बोट एवं एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड विदिशा की 3 बोट और 30 जवानों द्वारा संयुक्त खोजबीन की गई। आज रविवार 27 जुलाई को उक्त महिला के शव की बरामदगी कुरवाई के वाटर फिल्टर प्लांट के पास होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ विदिशा की टीम द्वारा सघन सर्चिंग अभियान के दौरान की गई तथा उसे विधिसंगत कार्यवाही हेतु पुलिस के सुपुर्द किया गया। उक्त सर्चिंग अभियान में एनडीआरएफ टीम की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने विशेष तकनीकी उपकरणों एवं प्रशिक्षण के माध्यम से खोज कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित किया। प्रशासन की ओर से महिला के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

जिले में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं रासायनिक उर्वरक

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में उर्वरक वितरण संबंधी प्रक्रिया का प्रभावी संचालन किया जा रहा है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को परेशान नहीं होना पड़े। इस संबंध में कृषि विभाग के उप संचालक श्री अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि जिले में वर्तमान में खरीफ फसलों की लगभग 95 प्रतिशत तक बोनी पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2025-26 में जिले के लिए 65,000 मे.टन यूरिया, 25,000 मे.टन डी.ए.पी., 25,000 मे.टन एस.एस.पी. एवं 17,000 मे.टन एन.पी.के. उर्वरकों की मांग की गई थी, जिसमें से अभी तक 44,930 मे.टन यूरिया, 13,300 मे.टन डी.ए.पी., 16,200 मे.टन एस.एस.पी. एवं 7,700 मे.टन एन.पी.के. जिले की सहकारी संस्थाओं एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को वितरित किया जा चुका है।

लंबित आवेदनो की समीक्षा

रोपित पौधो के फोटोग्राफ्स जियो टैग सहित उपलब्ध कराएं : कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को लंबित आवेदनो की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम, मानव अधिकार आयोग सहित अन्य आयोगो से प्राप्त आवेदनो के अलावा वरिष्ठ कार्यालयों और जन सुनवाई कार्यक्रम के लंबित आवेदनो पर विभागीय अधिकारियों द्वारा विभागवार निराकरण की अद्यतन जानकारियां प्राप्त की है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सभी विभागो के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आवेदनो का स्वंय कम से कम पांच आवेदको से हर रोज संवाद करें ताकि निराकरण को गति मिल सकें। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज आवेदनो का मतलब यह नहीं कि हम प्रदेश स्तरीय रैकिंग सूची में स्थान हासिल करें बल्कि आवेदक की समस्या का निदान कर उनके विश्वास पर शासन प्रशासन खरा उतरे यहीं प्रमुख उद्धेश्य होना चाहिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने सीएम हेल्पलाइन

और समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम के सम्मिलित विषयों को क्रियान्वित कराने वाले विभागो की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में जिन विषयों को शामिल किया गया है उन बिन्दुओं पर आधारित एक भी आवेदन लंबित ना रहें ताकि समाधान ऑन लाइन कार्यक्रम में जिले का एक भी आवेदन उस स्तर तक ना पहुंचे कि मुख्यमंत्री जी को आवेदक से संवाद कर निराकरण कराना पडे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले में जारी एक पेड़ मां के नाम अभियान तहत रोपित किए जाने वाले पौधो के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभागवार तय किए गए लक्ष्यों की उपलब्धियों का जायजा लिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियो को निर्देशित किया है कि जो भी पौधे लगाए जाते है उसकी जानकारी सम्पूर्ण रिकार्ड संधारित किया जाए जिसमें कहा लगाए गए, कौन सी प्रजाति के पौधे है, सुरक्षा के उपाय, ग्रीष्मकाल के दौरान पानी देने की व्यवस्था इत्यादि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित हो। कलेक्टर श्री गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पौधरोपण कार्यो को जहां-जहां किया जाता है उन क्षेत्रो में रोपित पौधो के फोटोग्राफ्स जियो टेग सहित संधारित किए जाएं। उक्त रिकार्ड को जिला पंचायत में व्यवस्थित रूप से रखे जाने के निर्देश दिए गए है। समीक्षात्मक बैठक में विभागवर लगाए गए पौधो की संख्या में से संबंधित विभाग के जिलाधिकारी द्वारा जानकारियां सांझा की गई। कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर समेत विभिन्न विभागो के जिलाधिकारी मौजूद रहे जबकि खण्ड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से संवाद किया गया है।

पीएम उज्ज्वला योजना ने बदली श्रीमती भारती जैसी लाखों महिलाओं की जिंदगी

सीहोर (निप्र)। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी उन्हीं योजनाओं में से एक हैं। यह योजना केवल एक गैस कनेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लाखों महिलाओं के जीवन में आत्मसम्मान, स्वच्छता और सशक्तिकरण की अलख जगा चुकी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। यह योजना स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक लक्ष्यों को एक साथ साधती है। सीहोर निवासी श्रीमती भारती दीक्षित भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिला है। श्रीमती भारती कहती हैं कि पहले वे परंपरागत चूल्हे पर लकड़ी और उपलों से खाना बनाती थीं, जिससे धुएं की वजह से उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याएं हो रही थीं। आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और रसोईघर में जमा कालिख उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन उज्ज्वला योजना उनके लिए एक वरदान साबित हुई।

मन की बात कार्यक्रम बज्जरवाडा में हुआ सम्पन्न

बैतूल (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का जिले के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के ग्राम बज्जरवाडा में विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय ग्रामीणों ने सहभागिता कर प्रधानमंत्री जी के विचारों का श्रवण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक बैतूल श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक घोड़ाडोंगरी श्रीमती गंगाबाई उईके, जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) श्री मोहन नागर, पूर्व बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष श्री राघवेंद्र शर्मा, समाजसेवी एवं शिक्षाविद श्रीमती ऋतु खंडेलवाल, श्री सुधाकर पवार, सरपंच श्रीमती स्नेहलता इवने, कमलेश सिंह, श्री नंदन यादव, श्री रामसिंह काकोडिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम हमेशा समाज और संस्कृति के लिए प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और समूहों का उल्लेख किया गया, जो हम सभी के लिए मार्गदर्शक हैं। विधायक खंडेलवाल ने जानकारी दी कि बैतूल जिले की स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर एक केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही ग्राम स्तर पर विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए बज्जरवाडा और बांचा की तर्ज पर अन्य गांवों में भी होम स्टे विकसित किए जाएंगे, ताकि पर्यटक जनजातीय परंपराओं से परिचित हो सकें।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत

10 टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान कलेक्टर ने नागरिको से जिले को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की

नर्मदापुरम (निप्र)। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नर्मदापुरम जिले में सभी विकासखण्डों में टीबी स्क्रीनिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में 306000 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 54986 लोगों की टीबी स्क्रीनिंग टीबी स्टाफ, सीएचओ, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता द्वारा की जा चुकी है। सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गेहलोत के मार्गदर्शन में सोमवार 28 जुलाई को जिला क्षय केंद्र में 10 टीबी मरीजों को फूड बास्केट प्रदान की गई।

इस अवसर पर जिला क्षय अधिकारी, डॉ संजय पुरोहित एमओडीटीसी, विशेष दुबे डीपीसी, हेमन्त अग्रवाल, श्याम वर्मा, चंदा शेख, वर्षा शर्मा सहित एनएचएम कार्यालय का समस्त स्टॉफ उपस्थित रहा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत केन्द्रीय जेल, छात्रावासों, रेन बसेरों और अन्य स्लम क्षेत्रों में टीबी स्क्रीनिंग शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। जिले में अब तक 158 निक्षय मित्र बनाए जा चुके हैं, जो टीबी मरीजों को स्वेच्छिक फूड बास्केट वितरण कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को 1000 प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से इलाज पूर्ण होने तक दिए जा रहे हैं। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना एवं सीएमएचओ डॉ. नरसिंह गेहलोत द्वारा टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग नागरिक, सभी डायबिटिक मरीज, सभी धूम्रपान वाले नागरिक, पुराने टीबी मरीज के संपर्कित व्यक्ति जिनका बीएमओ 18 से कम है, साथ ही टीबी के लक्षण जैसे सर्दी जुकाम खाँसी वाले नागरिकों से अपील की गई है कि वे नजदीकी स्वास्थ्य संस्था में जाकर टीबी की स्क्रीनिंग निःशुल्क करायें एवं जिले को टीबी मुक्त जिला बनाने में सहयोग करे।

"विधिक साक्षरता से सशक्त बनता है समाज"

सन्यासा, गोंदागांव कला छिपानेर में विधिक जागरूकता शिविर सम्पन्न

हरदा (निप्र)। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष श्रीमती तृप्ति शर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार को माध्यमिक शाला सन्यासा, शासकीय नवीन माध्यमिक शाला गोंदागांव कला, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला छिपानेर में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश एवं सचिव श्री चंद्रशेखर राठौर ने बताया कि बाल अधिकार जागरूकता अभियान बच्चों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जागरूकता बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल यौन शोषण बाल विवाह, बाल श्रम आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होने यह भी बताया कि नालसा ''डॉन स्कीम'' राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा द्वारा नशा उन्मूलन के लिये शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य, विशेष रूप से युवा व किशोरों में नशीले पदार्थों के उपयोग के विरूध्द जागरूकता बढ़ाना और नशे के शिकार लोगों को कानूनी सहायता और कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करना है। श्री राठौर ने शिविर में नालसा नशा पीड़ितो को विधिक सेवाऐं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाऐं योजना के उपबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत ड्रग्स तस्करी एवं ड्रग्स पीड़ितों को जिला प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है। योजना के तहत ड्रग्स पीड़ितों को पहचानने, उनका उपचार करने तथा नशा मुक्ति के पश्चात उनके

पुनर्वास में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं को गतिमान कराया जाता है। साथ ही ड्रग्स के खतरों एवं इसके उन्मूलन के प्रभावी उपायों के विषय में संवेदनशील बनाया जाता है। जिला प्राधिकरण एवं राज्य की कई एजेन्सियों के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी नशीले पदार्थो की तस्करी और मादक पदार्थो के उन्मूलन के क्षेत्र में कार्यरत है। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने नालसा बच्चों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना के तहत ''पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो रूल्स तथा प्रतिकर'' से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों एवं मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा लैंगिक हमलों अन्य अपराधों की पीड़िताओं सर्वाईवर्स महिलाओं के लिए प्रतिकर योजना की जानकारी उपस्थितजनों को दी। इस अवसर पर ''पंच-ज'' अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण को हरा भरा और स्वस्थ बनाना है वृक्षारोपण हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिविर में ग्राम पंचायत सन्यासा के सह सचिव श्री महेन्द्र राजपूत, ग्राम पंचायत गोंदागांव के सचिव श्री धर्मेंद्र लाठी एवं ग्राम पंचायत छिपानेर के सचिव श्री लक्ष्मण बिल्लौरे, ग्रामीणजन एवं पैरालीगल वॉलेंटियर श्री राहुल जाट उपस्थित रहे।

सक्षम कार्यक्रम के तहत शिक्षक अभिविन्यास प्रशिक्षण आयोजित

बैतूल (निप्र)। जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश द्वारा संचालित 'सक्षम'जीवन कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम राइज विद्यालय शाहपुर में एक दिवसीय शिक्षक अभिविन्यास रिफ्रेशर प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे बैचवार आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य वर्ष 2 के मॉड्यूल की नवाचारों एवं उद्देश्यों से शिक्षकों को परिचित कराना था। प्रशिक्षण की शुरुआत ब्लॉक प्रबंधक द्वारा मीना सातनकर और इंद्रसेन नागले प्री-टेस्ट से हुई, जिसके बाद वर्ष 1 एवं वर्ष 2 के मॉड्यूल की संरचना एवं मुख्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। मास्टर ट्रेनर राजेश भट्ट, गणेश कुमरे ने पूर्व वर्षों की उपलब्धियों और अनुभवों का विश्लेषण प्रस्तुत किया। ब्लॉक प्रबंधक विद्या रैकवार ने जेंडर समानता और बाल संरक्षण के महत्व पर विशेष सेशन के माध्यम से शिक्षकों की समझ विकसित की। बाल दुर्व्यवहार के प्रकार व रोकथाम के लिए प्रभावी कदम भी सुझाए गए। मास्टर ट्रेनर फरीदा अली ने जीवन कौशल सत्रों का व्यवहारिक प्रदर्शन कर शिक्षकों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। जिला कार्यक्रम प्रबंधक निष्ठा सौदावत ने विद्यालय में मेरी सीख का कोना , सक्षम वॉल, बिहेवियर मैनेजमेंट सिस्टमजैसे नवाचारों को लागू करने हेतु मार्गदर्शन किया और 11 जीवन कौशलों की मेहता और बारीकियां पर चर्चा की गई।

आजिविका मिशन ने खोले भागवती अहिरवार के लिए आत्मनिर्भता के द्वार

बहुआयामी आजिविका गतिविधियों से जुड़ कर पारिवारिक आय में की वृद्धि

नर्मदापुरम (निप्र)। जिले के रायपुर गांव की रहने वाली श्रीमती भागवती अहिरवार ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। वर्ष 2019 में आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को न सिर्फ सुधारा, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्त्रोत बन गईं। शुरुआत में उनके परिवार का एकमात्र सहारा उनके पति की खेती-बाड़ी थी, जिससे गुजर-बसर मुश्किल से होता था। लेकिन समूह से जुड़ने के बाद आरसेटी (ऋस्थ्वञ्जद्ध) प्रशिक्षण संस्था नर्मदापुरम से उन्होंने सीएससी (ष्टस्ष्ट) कियोस्क आईडी चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद समूह से ऋण लेकर अपने ही गांव में एक सीएससी कियोस्क सेंटर की स्थापना की, जिससे उनकी आय 5,000 से 7,000 प्रतिमाह तक पहुंच गई। श्रीमती अहिरवार ने बहुआयामी आजीविका गतिविधियों के द्वारा बढ़ाये आत्मनिर्भरता की ओर कदम जिसमें सीएससी कियोस्क संचालन के लिए उन्होने आरसेटी से प्रशिक्षण लेकर सीएससी केंद्र शुरू किया जिससे उन्हें निरंतर आय हो रही है। इसी के साथ बैंक सखी एवं बीसी सखी बनने के लिए भागवती अहिरवार ने बैंक सखी प्रशिक्षण प्राप्त कर मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, मालाखेड़ी शाखा में कार्य प्रारंभ किया, जिससे उन्हें 3 हजार से 4 हजार तक की मासिक आमदनी हो रही है। जिला आजीविका मिशन से जुड़े ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यों को करते हुए उन्हें 3 हजार की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। श्रीमती अहिरवार के पति ने समूह के माध्यम से ऋण प्राप्त कर कृषि कार्य को और अधिक विस्तार दिया, जिससे पारिवारिक आय में स्थायित्व आया। भागवती अहिरवार को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने अपने गांव की महिलाओं को भी इस योजना के बारे में जागरूक कर योजना का लाभ दिलवाया। समूह की नियमित बैठकों में भाग लेने से भागवती अहिरवार का आत्मविश्वास बढ़ा है। आज वे आजीविका मिशन की सक्रिय सदस्य हैं और विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों से हर माह सतत आय अर्जित कर रही हैं। उनका कहना है कि आजीविका मिशन से जुड़ना उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय रहा, जिसने उनके पूरे परिवार की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया।

लव जिहाद की फंडिंग का आरोपी पार्षद गिरफ्तार

इंदौर पुलिस को कश्मीर में मिला; हिंदू लड़की फंसाने के एक लाख, निकाह के दो लाख देता था

भोपाल। लव जिहाद के लिए फंडिंग के आरोपी इंदौर के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पुलिस ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया है। उस पर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए एक लाख और निकाह करने के लिए दो लाख रुपए मुस्लिम युवकों को देने के आरोप हैं। पुलिस ने इससे पहले सोमवार को अनवर की बेटी आयशा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी थी, तब अनवर फरार हो गया था। उसे श्रीनगर पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। हालांकि, इंदौर पुलिस ने अनवर की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।

बेटी आयशा दिल्ली में अपने पिता अनवर कादरी की सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर तैयारी कर रही थी। उसने वहां जमानत के दस्तावेज भी तैयार कराए थे, जिन पर अनवर के हस्ताक्षर हो गए थे। पुलिस को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस को शंका हुई थी कि अनवर बेटी के पास दिल्ली में है और टीम वहां पहुंच गई। सोमवार को आयशा की गिरफ्तारी से पहले कई महिलाएं क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थीं। उनका आरोप था कि बेटियों को जबरन फंसाया जा रहा है। अनवर की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते पुलिस अब परिवार को निशाना बना रही है। अनवर कादरी के परिवार के लोगों का कहना है कि आयशा की गिरफ्तारी कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है। वह वकील होने के नाते जमानत की अर्जी की तैयारी कर रही थी, ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आयशा खुद पेशे से वकील है और दिल्ली में रहकर सिविल जज की पढ़ाई की तैयारी कर रही है। उसकी छोटी बहन भी दिल्ली से वकालत की तैयारी कर रही है। पुलिस को मोबाइल में अनवर के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं मिली, तो उसे वहीं छोड़ दिया गया। छोटी बहन ने ही इंदौर में परिवार को आयशा के पकड़े जाने की जानकारी दी थी। बाणगंगा पुलिस को फिलहाल आयशा का 3 अगस्त तक का रिमांड मिला हुआ है।

इंदौर पुलिस ने साहिल शेख और अल्ताफ के खिलाफ दो युवतियों के साथ रेप और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान सामने आए वीडियो में दोनों आरोपियों ने कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम लिया, जिस पर उन्हें लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने और निकाह के लिए पैसों का लालच देने का आरोप है। पुलिस को मिले वीडियो साक्ष्यों और आरोपियों के बयान के आधार पर पार्षद अनवर कादरी का नाम एफआईआर में जोड़ा गया था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने सोशल मीडिया पर फर्जी हिंदू नामों से आईडी बनाकर युवतियों से संपर्क किया था। मोबाइल जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वे 'अर्जुन' और 'राज' जैसे नामों का इस्तेमाल कर लड़कियों से दोस्ती करते और फिर उन्हें बहलाकर मुलाकात के लिए बुलाते थे। इसके बाद शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। साहिल शेख और अल्ताफ ने पुलिस को बताया था कि अनवर ने युवकों को एक लड़की को फंसाने के लिए एक लाख रुपए और निकाह कराने पर दो लाख रुपए देने की बात कही थी। जांच में पता चला था कि यह एक संगठित गिरोह की साजिश हो सकती है। पुलिस इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है और आगे जल्द ही बड़े खुलासे संभव हैं। एडिशनल डीसीपी रामसनेही मिश्रा ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ से गलत तरीके से एक आर्म्स लाइसेंस अनवर के नाम से जारी किया था।

इस लाइसेंस को सस्पेंड किया है। कुछ फर्म और एसोसिएट्स भी सामने आए हैं। 3 बैंक अकाउंट और एक फिशरिस फर्म की जानकारी भी मिली है। जांच में खुलासा हुआ है कि एक संगठित अपराध किया जा रहा है। इनलीगल तरीके से फंडिंग की जानकारी मिली है। पुलिस व्यावसायिक साझेदारी में शामिल लोगों तक पहुंची है। संकेत मिले हैं कि इस मामले में कई लोग शामिल हैं। 2011 में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, उसके भाई और एक अन्य आरोपी को जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई थी। यह हमला 6 मई 2009 को इंदौर के आजादनगर चौराहे के पास अनवर हुसैन पर किया गया था। अनवर हुसैन आरोपियों पर चल रहे एक अन्य मामले में गवाह था। पुलिस ने कादरी समेत कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

विधानसभा में कांग्रेस एमएलए ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

कहा-प्रदेश में ट्रांसफर के नाम पर हो रही है वसूली, साल भर भी नहीं चल रहीं सड़क

- भाजपा विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए, विपक्ष को विकास के लिए नहीं दे रहे राशि

भोपाल। एमपी विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन था। सदन में आज 4 विधेयक पेश किए गए हैं। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने तीन विधेयक पटल पर रखे। अनूपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आरोप लगाया कि ट्रांसफर के नाम पर वसूली की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्ताधारी दल के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही, जबकि विपक्षी विधायकों को विकास के लिए राशि नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि पहले सड़कें बनती थीं तो कम से कम एक बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब 40 दिन में सड़कें उखड़ रही हैं। जबलपुर की सड़कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 56 करोड़ की सड़क इसी बारिश में बह गई। अधिकारी दिखावे की कार्रवाई करते हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पेसा कानून को सही तरीके से लागू न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार पर आदिवासियों को वन क्षेत्र से बेदखल किए जाने का आरोप लगाया। इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- मुझे लगता है कि जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया उन्हें मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पेसा के मामले में जिस ढंग से काम हुआ है वह बेहतरीन है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अनुमति के बाद आज 4 विधेयक सदन में पेश किए गए। भाजपा विधायक डॉ. अभिलाष पांडे ने मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा में किए गए सवाल में से मूल प्रश्न को बदलने का आरोप लगाया। कार्यवाही शुरू होने से पहले पेसा कानून को ठीक से लागू नहीं किए जाने को लेकर विपक्षी विधायकों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- सरकार आदिवासियों को परेशान कर रही है। वन विभाग उन्हें वन क्षेत्र से बेदखल करने में जुटा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा- ये हालात पूरे प्रदेश में है। ये केवल आश्वासन और घोषणाओं की सरकार है। बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा- हमारी सरकार आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली है, जबकि कांग्रेस पाखंड करती है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा- मुझे लगता है जिन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, उन्हें मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पेसा के मामले में बेहतरीन काम हुआ है। कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने अपने क्षेत्र के एसडीएम का जिक्र करते हुए कहा कि वन अधिकार पट्टे देने के मामले में एसडीएम धमकी देते हैं। कहा जाता है कि वॉशिंग मशीन से होकर गुजर जाइए आपके सारे काम होते जाएंगे। विधायक ने कहा- जो पहले से पीढ़ियों से काबिज रहे हैं, उन्हें 2006 में नाबालिग होने के चलते अपात्र घोषित कर दिया गया। 2006 में बहुत से बच्चे नाबालिग थे और अब 18 साल की उम्र होने पर बालिग हो गए हैं, लेकिन उन्हें अपात्र बताया जा रहा है। विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने कहा कि मजदूर मजदूरी कर नहीं पा रहे। आउटसोर्स के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं और पैसा मांगते हैं तो समय पर नहीं देते। आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी काम न करें तो मंत्रालय और दूसरे विभागों में काम पूरा नहीं हो पाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र में भवन, उपचार की सुविधा, पीने का पानी उचित व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। विधायकों के साथ अन्याय हो रहा है। सत्ता पक्ष के विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और विपक्ष के विधायकों को विकास के लिए राशि नहीं दी जा रही है। सरकार अगर 15 करोड़ विपक्ष के विधायकों को नहीं देगी तो हम संघर्ष करेंगे और सरकार नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि चार करोड़, दस करोड़ की वसूली ट्रांसफर के माध्यम से की जा रही है। विधायक मरकाम ने कहा कि ट्रांसफर उद्योग के नाम पर एक नया फंड जनरेट हो गया है। ट्रांसफर उद्योग चलाने से अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर सिरोंज के बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा ये चाहे भैंस बन जाएं या गिरगिट बनें या पत्ते पहन कर आएं। पेसा का कानून भाजपा की सरकार ने ही लागू किया है।

विधायक चिटनीस बोलीं- खर्च को लेकर अफसरों से चर्चा की जानी चाहिए: अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए भाजपा विधायक अर्चना चिटनीस ने कहा कि साल भर में एक बार सभी संभागों के अफसरों को बुलाकर चर्चा की जानी चाहिए। इससे अनुपूरक बजट के साथ प्रदेश के बजट को लेकर खर्च की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि यशपाल सिंह सरकार की खूब पैरवी करते थे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए अब विधायक अर्चना कर रही हैं, इस पर विधायक चिटनीस ने कहा कि वह विधायक बनकर खुश हैं, मंत्री नहीं बनना चाहती। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने पौधारोपण पर होने वाले खर्च पर भी सवाल उठाए। जबलपुर की सड़कों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 56 करोड़ की सड़क इसी बारिश में बह गई है। घनघोरिया ने जबलपुर के ज्ञान गंगा रूप का जिक्र करते हुए कहा कि दिखावे के तौर पर कार्रवाई की जाती है। बड़े ग्रुपों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारी अपनी मर्जी से सिर्फ छपास की बीमारी के कारण ऐसा कर रहे हैं।

कांग्रेस विधायक ने कहा- 40 दिन में 40 लाख की सड़क उखड़ी

अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा कि सरकार 4 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज में है।

5 वर्षों बाद भी अधूरी पड़ी महेश्वर परियोजना

सचिन यादव ने विधानसभा में उठाए तीखे सवाल

- 10 हजार परिवार और करोड़ों की लागत पर अधर में लटकी
- महेश्वर परियोजना का मुद्दा विधानसभा में गूंजा
- महेश्वर परियोजना के पुनर्वास, कर्मचारियों के हक और संपत्ति नीलामी पर मांगा जवाब

भोपाल। विधानसभा सत्र के दौरान महेश्वर जल विद्युत परियोजना का मामला गरमाया, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कसरावद विधायक सचिन यादव ने सरकार को घेरा। श्री यादव ने आज बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में महेश्वर जल विद्युत परियोजना के अधूरेपन और उससे जुड़े जनसरोकारों को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया। सचिन यादव ने ध्यानाकर्षण याचिका के माध्यम से यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठाते हुए बताया कि यह परियोजना 35 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी और इसमें जनता की लगभग 3,000 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। वर्तमान में इसकी कीमत 9,500 करोड़ रुपये तक पहुँच चुकी है, बावजूद इसके यह परियोजना बंद पड़ी हुई है और इससे जुड़े लगभग 10,000 परिवार व सैकड़ों कर्मचारी आज भी अनिश्चितता में बदहाली का जीवन यापन कर रहे हैं।

प्रमुख बिंदु जो विधायक द्वारा उठाए गए

1. डूब प्रभावित सैकड़ों गांव आज भी पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं।
2. प्रभावितों को आवासीय प्लॉट आवंटित तो किए गए हैं लेकिन आज तक उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है।
3. परियोजना के कर्मचारियों व अधिकारियों को वेतन नहीं मिला, जिससे अधिकांश ने परियोजना स्थल छोड़ दिया है और वह अब लावारिस स्थिति में पड़ा है।
4. सरकार ने परियोजना से जुड़ी संपत्तियों की नीलामी की बात तो कही है लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि उस राशि का उपयोग कहां और कैसे होगा।
5. परियोजना को 2020 में बंद घोषित किया गया, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे पुनः प्रारंभ किया जाएगा या नहीं।
6. डूब प्रभावित क्षेत्रों को ग्राम पंचायतों को कब तक हस्तांतरित किया जाएगा और मूलभूत सुविधाएं कब तक पूरी होंगी क्या इन प्रश्नों का भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।
7. विधायक ने सरकार से यह भी पूछा कि इन गांवों के लिए कोई विशेष पैकेज देने की योजना है या नहीं।

एमपी में महिला जज ने जाहिर किया अपना दर्द, दे दिया इस्तीफा

भोपाल। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पदस्थ सिविल जज अदिति कुमार शर्मा ने न्यायिक सेवा से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के साथ ही उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि अदिति कुमार शर्मा ने एक न्यायिक अधिकारी को हाईकोर्ट में पदोन्नत किए जाने के विरोध में दिया है। अदिति कुमार शर्मा ने उस अधिकारी पर पहले यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अब उन्हें हाईकोर्ट जज के रूप में पदोन्नति मिली तो महिला जज ने इस्तीफा दे दिया। वहीं, अपने इस्तीफे में जज शर्मा ने लिखा है कि यह फैसला संस्थागत विफलता के खिलाफ एक विरोध है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा इस बात का सबूत है कि मध्य प्रदेश में एक महिला जज थी जो न्याय के लिए समर्पित थी लेकिन संस्था ने उसका साथ नहीं दिया। हालांकि जिनके पदोन्नति के विरोध में जज अदिति कुमार शर्मा ने इस्तीफा दिया, उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है। जज अदिति कुमार शर्मा ने अपना अपना इस्तीफा एमपी के चीफ जस्टिस को भेज दिया है। उन्होंने लिखा है कि यह फैसला उनके व्यक्तिगत दर्द की वजह से नहीं है। यह संस्थागत विफलता के विरोध में है। अदिति कुमार शर्मा ने लिखा है कि मैंने न्याय से भरोसा नहीं खोया है बल्कि उस प्रणाली से टूट चुकी हूं जो न्याय की सबसे बड़ी संरक्षक होने का दावा करती है। उन्होंने

अपने इस्तीफे में यह भी लिखा कि उनका इस्तीफा हमेशा इस बात की गवाही देगा कि मध्य प्रदेश में एक महिला जज थी। वह न्याय के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। लेकिन उसी संस्था ने उसका साथ नहीं दिया। गौरतलब है कि जज अदिति कुमार शर्मा उन छह महिला न्यायिक अधिकारियों में शामिल थीं, जिन्हें जून 2023 में असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। यह फैसला हाईकोर्ट की प्रशासनिक और पूर्ण पीठ की बैठकों के आधार पर लिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देते हुए सभी को बहाल कर दिया था। जज शर्मा ने मार्च 2024 से शहडोल में दोबारा काम शुरू किया था। वहीं, जुलाई 2025 में जज अदिति कुमार शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को कॉलेजियम पर पत्र लिखा था। उन्होंने उस अधिकारी की पदोन्नति पर दोबारा विचार करने को कहा था। जज शर्मा ने कहा कि जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें बिना किसी जांच के पदोन्नत करना न्यायपालिका की जवाबदेही और संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा करता है। जज शर्मा ने यह भी कहा कि यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत मामला नहीं है। बल्कि, यह न्यायिक संस्थान की चुप्पी और उदासीनता का मामला है। जज शर्मा की शिकायत के अलावा, दो अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी उसी अधिकारी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई थीं। वहीं, पदोन्नति को मंजूरी दिए जाने से पहले, संबंधित अधिकारी ने सभी आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उन्होंने तीन दशकों से अधिक सेवा की है और उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें किसी शिकायत के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इसके साथ ही जज अदिति कुमार शर्मा ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान बार-बार शिकायतें दर्ज कराई। लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही जांच बैठाई गई। सिस्टम ने कार्रवाई की जगह उस अधिकारी को पदोन्नति दी है।

मुंह से 'अल्लाह कसम' निकलते ही दुल्हन 'बेनकाब'

शादीशुदा नाजिया ने ब्राह्मण बनकर हिंदू लड़के से रचाई थी शादी

भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह एक युवक की शादी विवाहित महिला को अविवाहित बताकर करवा दी गई है। यही नहीं, दुल्हन बनकर आई महिला का एक पांच साल का बच्चा भी है। पूरा परिवार तब सन्न रह गया, जब दुल्हन के मुंह से एक दिन अल्लाह निकल गया। जबकि शादी ब्राह्मण युवती से हुई थी। पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। इंदौर पीड़ित परिवार के होश उस वक्त उड़ गए, जब दुल्हन की जुबां से लोगों ने अल्लाह का नाम सुना।

शादी करवाने वालों ने उसकी जाति ब्राह्मण बताई थी। साथ ही नाम निकिता बताया था। मुंह से अल्लाह निकलने के बाद पता चला कि दुल्हन का असली नाम नाजिया है। सच्चाई सामने आने के बाद वह ससुराल से ढाई-तीन लाख रुपए लेकर फरार हो गई। दरअसल, गांधी नगर थाना क्षेत्र स्थित हिंगोनिया खुर्द गांव का एक परिवार अपने बेटे की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा था। युवक के भाई की मुलाकात मुकेश मराठा नाम के आदमी से हुई। उसने शादी करवाने के लिए 20 हजार रुपए लिए और आष्ट्रा की लड़की के बारे में बताया। साथ ही युवक को उस लड़की से मिलवाया भी। पहले युवक की शादी 26 फरवरी 2024 को तय हुई थी। परिवार में शादी की पूरी तैयारी हो गई है। इस दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने यह बताकर शादी कैंसिल कर दी कि दुल्हन का एक्सीडेंट हो गया है। इस दौरान मुकेश ने कोमल और नेहा नाम की दो लड़कियों से मुलाकात करवाई। कोमल ने फिर पीड़ित परिवार से ढाई लाख रुपए लिए और शादी के लिए निकिता नाम की लड़की से मिलवाया। साथ ही कहा कि यह ब्राह्मण समाज की है। युवक की शादी निकिता से करवा दी गई। शादी के बाद बातचीत के दौरान निकिता के मुंह से कई बार अल्लाह कसम और या अल्लाह निकल गई। यह सुनकर परिवार वाले हैरान रह जाते। बार-बार ऐसे शब्द सुनने के बाद उन्हें शक हुआ और पूछताछ शुरू कर दी। निकिता ने अपना असली नाम नाजिया बताया। इसी बीच वहां कोमल पठान पहुंचती है और नाजिया को साथ ले जाती है। तीन दिन बाद नाजिया फिर वापस ससुराल लौट आई। इस दौरान ससुराल के लोगों से कहा कि वह हमारी शादी दूसरी जगह करवाने ले गई थी लेकिन हमने मना कर दिया।

अब वापस आ गई हूं। इसके बाद जसवंत के पास शाहनवाज उर्फ शानू नाम के एक व्यक्ति का फोन आया। उसने बताया कि वह नाजिया का पति है और उनका 5 साल का एक बच्चा भी है। यह सुनकर परिवार हैरान रह गया। इसके बाद नाजिया अचानक घर से सारा सामान लेकर फरार हो गई। युवक ने जब नाजिया के परिवार के बारे में पता किया तो मालूम चला कि वह नायता मुंडला में एक किराए के मकान में रहने लगी है। नाजिया का बच्चा भी उसके साथ है। जब युवक ने नाजिया की मां से बात की तो वह भी उसे भूल जाने की बात कहकर धमकाने लगी। युवक के परिवार ने इस बारे में परशुराम सेना के पदाधिकारियों को बताया। एडवोकेट नमन दुबे ने कहा कि युवक ने इस मामले की शिकायत गांधीनगर पुलिस से की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद परशुराम सेना के पदाधिकारियों के साथ पीड़ित युवक पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा।

मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर में कांग्रेस विधायकदल का जोरदार प्रदर्शन आदिवासी अधिकारों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा

तीसरे दिन गले में पत्तों की माला पहनकर पहुंचे विधायक,

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार के नेतृत्व में आदिवासी अधिकारों को लेकर विधानसभा परिसर में जोरदार और प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने पत्तों से बनी मालाएं पहनकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। भाजपा सरकार आदिवासियों को वन पट्टों का अधिकार देना ही नहीं चाहती। प्रदेश में आदिवासियों की जमीनों से बेदखली की जा रही है, वन पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं, पेसा कानून को जमीन पर लागू नहीं किया जा रहा है और आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। उमंग

सिंघार ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों के भूमि पट्टे निरस्त किए जा रहे हैं, जबकि 2006 के पहले से जमीन पर बसे हुए आदिवासियों को नियमानुसार पट्टे दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आदिवासी कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को सुझाव दिया कि गूगल मैप और गूगल इमेजिंग जैसी तकनीकों का उपयोग कर यह प्रमाणित किया जा सकता है कि कौन आदिवासी कब से किस जमीन पर रह रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आदिवासियों के हक और अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेगी। यह प्रदर्शन सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों और असंवेदनशील रवैये के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जनपक्षधर राजनीति का एक अहम हिस्सा था। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद रहे।